

प्रगति पथ पर
गतिमान राजस्थान

शहरी विकास को नई रफ्तार - आधुनिक राजस्थान की नई पहचान

मजबूत सड़कें • सुगम यातायात • बेहतर ड्रेनेज • आधुनिक सीवरेंज • सुरक्षित सबवे • बेहतर मेडिकल सुविधाएं • श्रमिक कल्याण • स्वच्छ एवं हरित परिवहन

राजस्थान के शहरों को मिल रही ₹2,340 करोड़ की सौगातें
941 कार्यों का शिलान्यास-लोकार्पणश्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं के
1 लाख 32 हजार 421 लाभार्थियों को ₹154 करोड़ से अधिक की सहायता राशि की डीबीटी

स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की दिशा में जयपुर को बड़ी सौगात

लोकार्पण

RUHS जयपुर : 128-स्लाइस CT स्कैन मशीन

जनाना चिकित्सालय, चांदपोल : नवीन आईपीडी टावर

SMS अस्पताल :

आयुष्मान टावर अंतर्गत कार्डियोवैस्कुलर साइंसेज संस्थान

RUHS जयपुर :

1.5 टेस्ला MRI मशीन तथा नवीन स्नातक छात्रावास

जयपुर जिले में झोटवाड़ा के अभयपुरा के उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं दूदू विधानसभा क्षेत्र के उप स्वा. केन्द्र, रेहलाना का निर्माण कार्य

शिलान्यास

जयपुर जिले के झोटवाड़ा में सैटेलाइट चिकित्सालय

पीएम ई-बस योजना

71 ई-बसों का शुभारंभ

जयपुर एवं भीलवाड़ा की 24 ई-बसों का जयपुर से
तथा अलवर, अजमेर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर से 47 ई-बसों का वर्चुअल शुभारंभ



वंदे मातरम् का गायन राष्ट्रीय स्तर पर राजनैतिक मुद्दा बनता जा रहा है

भाजपा इस बात को बड़े ध्यान से देख रही है कि कानून पास होने के बाद किसी भी स्तर पर वंदे मातरम् की अवहेलना तो नहीं हो रही है

-रेणु मि्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 17 अगस्ता क्या अमित शाह हताश हैं या उन्हें पता ही नहीं कि कहाँ रुक जाना चाहिए? या फिर वे कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करके अपना खोया हुआ राजनीतिक प्रभाव वापस हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं?

कहानी 1897 से शुरू होती है, जब कांग्रेस के एक अधिवेशन में पूरा वंदे मातरम् बिना किसी झिझक या समस्या के गाया गया था।

यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा।

1930 के दशक में, जब कांग्रेस ने स्वतंत्रता आंदोलन की और तेज कर दिया था, तब कुछ नेताओं ने वंदे मातरम् के तीसरे अंतरे पर आपत्ति जतानी शुरू की। इस अंतरे में मूर्ति पूजा का वर्णन था, जिसे इस्लाम धर्म में मान्यता नहीं है।

इस विवाद को ध्यान में रखते हुए जवाहरलाल नेहरू ने रवीन्द्रनाथ टैगोर को पत्र लिखा। उन्होंने पूरे विवाद का समाधान सुझाया।

यह विवाद 1937 में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक हुई, जिसमें पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। इनमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेन्द्र प्रसाद, राजगोपालाचारी और कई अन्य नेता मौजूद थे।

रवीन्द्रनाथ टैगोर से भी दोबारा सलाह ली गई। उन्होंने कहा कि जिस विवरण देते हुए पूछा कि सभी पक्षों को संतुष्ट रखने और हिंदू-मुस्लिम टकराव को और बढ़ने से रोकने के लिए क्या रास्ता अपनाया जाना चाहिए।

अक्टूबर 1937 में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक हुई, जिसमें पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। इनमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेन्द्र प्रसाद, राजगोपालाचारी और कई अन्य नेता मौजूद थे।

रवीन्द्रनाथ टैगोर से भी दोबारा सलाह ली गई। उन्होंने कहा कि जिस विवरण देते हुए पूछा कि सभी पक्षों को संतुष्ट रखने और हिंदू-मुस्लिम टकराव को और बढ़ने से रोकने के लिए क्या रास्ता अपनाया जाना चाहिए।

अक्टूबर 1937 में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक हुई, जिसमें पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। इनमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेन्द्र प्रसाद, राजगोपालाचारी और कई अन्य नेता मौजूद थे।

रवीन्द्रनाथ टैगोर से भी दोबारा सलाह ली गई। उन्होंने कहा कि जिस विवरण देते हुए पूछा कि सभी पक्षों को संतुष्ट रखने और हिंदू-मुस्लिम टकराव को और बढ़ने से रोकने के लिए क्या रास्ता अपनाया जाना चाहिए।

- कांग्रेस ने भी मान लिया है, जैसा राहुल गांधी ने भी कहा है, कि कानून बनने के बाद वंदे मातरम् को पूरा गाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, फिर भी थोड़ी बेचैनी सी है।
- सवाल यह है कि क्या वंदे मातरम् चुनावी मुद्दा बन सकता है, क्योंकि कांग्रेस मुसलमानों की सहानुभूति पाना चाहती है, वहीं भाजपा इस मुद्दे पर हिंदू वोटों का धुवीकरण करना चाहती है और वंदे मातरम् के संदर्भ में विपक्षी दलों की मामूली सी चूक को भी हवा दे रही है।
- इसी संदर्भ में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोनिया गांधी और कांग्रेस पर वंदे मातरम् के गायन में अड़ंगा डालने का आरोप लगाया और माफ़ी मांगने को कहा। यही नहीं, दिल्ली पुलिस से जाँच करने और रिपोर्ट देने को भी कहा है।

विवरण देते हुए पूछा कि सभी पक्षों को संतुष्ट रखने और हिंदू-मुस्लिम टकराव को और बढ़ने से रोकने के लिए क्या रास्ता अपनाया जाना चाहिए।

अक्टूबर 1937 में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक हुई, जिसमें पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। इनमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेन्द्र प्रसाद, राजगोपालाचारी और कई अन्य नेता मौजूद थे।

रवीन्द्रनाथ टैगोर से भी दोबारा सलाह ली गई। उन्होंने कहा कि जिस विवरण देते हुए पूछा कि सभी पक्षों को संतुष्ट रखने और हिंदू-मुस्लिम टकराव को और बढ़ने से रोकने के लिए क्या रास्ता अपनाया जाना चाहिए।

अक्टूबर 1937 में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक हुई, जिसमें पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। इनमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेन्द्र प्रसाद, राजगोपालाचारी और कई अन्य नेता मौजूद थे।

रवीन्द्रनाथ टैगोर से भी दोबारा सलाह ली गई। उन्होंने कहा कि जिस विवरण देते हुए पूछा कि सभी पक्षों को संतुष्ट रखने और हिंदू-मुस्लिम टकराव को और बढ़ने से रोकने के लिए क्या रास्ता अपनाया जाना चाहिए।

अक्टूबर 1937 में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक हुई, जिसमें पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। इनमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेन्द्र प्रसाद, राजगोपालाचारी और कई अन्य नेता मौजूद थे।

रवीन्द्रनाथ टैगोर से भी दोबारा सलाह ली गई। उन्होंने कहा कि जिस विवरण देते हुए पूछा कि सभी पक्षों को संतुष्ट रखने और हिंदू-मुस्लिम टकराव को और बढ़ने से रोकने के लिए क्या रास्ता अपनाया जाना चाहिए।

अक्टूबर 1937 में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक हुई, जिसमें पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। इनमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेन्द्र प्रसाद, राजगोपालाचारी और कई अन्य नेता मौजूद थे।

तीसरे अंतरे को लेकर विवाद पैदा हो रहा है, उसे हटा दिया जाना चाहिए। उनका तर्क था कि जब भारत स्वतंत्रता हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा है, तब सभी विवादाल्पद मुद्दों को अलग रख देना चाहिए।

टैगोर ने बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय से भी बात की। बंकिम चन्द्र ने कहा कि उन्हें किसी भी अंतरे को हटाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

इस तरह सभी पक्षों से विचार-विमर्श के बाद मामला सुलझा लिया गया और विवाद समाप्त हो गया।

लेकिन मोदी सरकार ने फैसला किया कि मुसलमानों को लगातार उकसाते रहना जरूरी है, ताकि हिंदू-मुस्लिम विभाजन पहले से कहीं अधिक गहरा हो सके।

मोदी सरकार ने एक कानून पारित किया, जिसके तहत पूरा वंदे मातरम् गाना अनिवार्य कर दिया गया और इसे न गाने पर सजा का प्रावधान किया गया।

15 अगस्त को कांग्रेस ने अपने नए (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

15 अगस्त को कांग्रेस ने अपने नए (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

15 अगस्त को कांग्रेस ने अपने नए (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मोदी सरकार ने एक कानून पारित किया, जिसके तहत पूरा वंदे मातरम् गाना अनिवार्य कर दिया गया और इसे न गाने पर सजा का प्रावधान किया गया।

15 अगस्त को कांग्रेस ने अपने नए (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मोदी सरकार ने एक कानून पारित किया, जिसके तहत पूरा वंदे मातरम् गाना अनिवार्य कर दिया गया और इसे न गाने पर सजा का प्रावधान किया गया।

15 अगस्त को कांग्रेस ने अपने नए (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मोदी सरकार ने एक कानून पारित किया, जिसके तहत पूरा वंदे मातरम् गाना अनिवार्य कर दिया गया और इसे न गाने पर सजा का प्रावधान किया गया।

15 अगस्त को कांग्रेस ने अपने नए (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मोदी सरकार ने एक कानून पारित किया, जिसके तहत पूरा वंदे मातरम् गाना अनिवार्य कर दिया गया और इसे न गाने पर सजा का प्रावधान किया गया।

मोदी सरकार ने एक कानून पारित किया, जिसके तहत पूरा वंदे मातरम् गाना अनिवार्य कर दिया गया और इसे न गाने पर सजा का प्रावधान किया गया।

विधानसभा सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आज

जयपुर, 17 अगस्ता सोलहवीं राजस्थान विधानसभा के षष्ठम सत्र की शुरुआत से पहले, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मंगलवार को प्रातः 11 बजे विधानसभा में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। 20 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अध्यक्ष देवनानी की अध्यक्षता में होने वाली यह सातवीं सर्वदलीय बैठक होगी। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जुली,

- स्पीकर देवनानी की अध्यक्षता में यह सातवीं सर्वदलीय बैठक है।

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सरकारी मुख्य सचिव जोगेश्वर गर्ग, मुख्य सचिव प्रतिपक्ष रफीक खान सहित, विभिन्न दलों के विधायकों को आमंत्रित किया गया है। देवनानी ने कहा कि विधानसभा जनहित के मुद्दों पर चर्चा का महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक मंच है। सदन की गरिमा बनाए रखना सत्ता पक्ष और विपक्ष सहित, सभी विधायकों की सामूहिक जिम्मेदारी है। सर्वदलीय बैठक के माध्यम से सभी दलों के बीच संवाद, समन्वय और विश्वास का वातावरण तैयार होता है। उन्होंने कहा कि आगामी सत्र में जनमहत्व के विषयों पर सार्थक चर्चा के लिए सकारात्मक वातावरण जरूरी है। सर्वदलीय बैठक के माध्यम से सदन की कार्यवाही को सुव्यवस्थित, गरिमापूर्ण और जनहित (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

“दिमागी नक्सल” कौन होता है? स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दिए अपने भाषण में प्र.मंत्री मोदी की “दिमागी नक्सल” टिप्पणी ने नई राजनैतिक बहस छेड़ दी है

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 17 अगस्ता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सरकार के विरोधियों के लिए दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल कई अन्य बातों के अलावा, भाजपा सरकार के रवैये में युवाओं के प्रति विरोधाभास को भी दर्शाता है।

एक ओर मोदी ने मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग, एआई कौशल प्रशिक्षण और नशामुक्त भारत जैसी घोषणाओं के जरिए युवाओं की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया और सरकार को महत्वाकांक्षी युवा भारतीयों के साथ खड़े साझेदार के रूप में पेश किया। दूसरी ओर, उन्होंने संकेत दिया कि इसी युवा वर्ग के एक भाग को दिमागी नक्सलियों द्वारा गुमराह करने या ब्रेनवॉश किए जाने का खतरा है और उसे मुख्यधारा में वापस लाने की जरूरत है।

इसका निहित संदेश साफ है: छात्रों को वास्तविक आकांक्षाओं का स्वागत

- प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिए कई योजनाएँ घोषित कीं, साथ ही यह भी कहा कि युवाओं के एक वर्ग का “दिमागी नक्सली” लोगों द्वारा “ब्रेन वॉश” किया जा रहा है, उन्हें गुमराह किया जा रहा है।

- विपक्षी नेताओं का कहना है कि प्र.मंत्री का इशारा स्वतंत्र विचारधारा और वामपंथी रुझान वाले छात्र संगठनों की ओर है और उनकी दिमागी नक्सल टिप्पणी सरकार की भावी दिशा का संकेत दे रही है।

है, लेकिन सरकार की आलोचना करने वाली या स्वतंत्र विचारधारा की छात्र राजनीति शक की नजर से देखी जाती है।

“दिमागी नक्सल” का तंत्र इस बात का संकेत भी है कि आने वाले महीनों में छात्र राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ सकती है। सभी संकेतों से लगता है कि एबीवीपी के लिए यह काफी सक्रिय दौर होने वाला है। परिसरों में अपनी पहुंच बढ़ाने, जवाबी लामबंदी करने और अपने विरोधियों को राट-

विरोधी या वैचारिक रूप से दूषित बताकर उन्हें निशाना बनाने की कोशिश तेज हो सकती है।

एबीवीपी खुद को युवा विकास की वैध आवाज के रूप में पेश करती रहेगी, जबकि वामपंथी रुझान वाले या स्वतंत्र छात्र संगठनों को बदनाम करने के लिए दिमागी नक्सल जैसे आरोपों का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि, अनुकूल रख रखने वाले युवाओं के लिए प्रोत्साहन और असहमति जताने वालों के लिए सख्ती

विरोधी या वैचारिक रूप से दूषित बताकर उन्हें निशाना बनाने की कोशिश तेज हो सकती है।

एबीवीपी खुद को युवा विकास की वैध आवाज के रूप में पेश करती रहेगी, जबकि वामपंथी रुझान वाले या स्वतंत्र छात्र संगठनों को बदनाम करने के लिए दिमागी नक्सल जैसे आरोपों का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि, अनुकूल रख रखने वाले युवाओं के लिए प्रोत्साहन और असहमति जताने वालों के लिए सख्ती

विरोधी या वैचारिक रूप से दूषित बताकर उन्हें निशाना बनाने की कोशिश तेज हो सकती है।

लेकर पार्टी के भरोसे का संकेत माना जा रहा है। राजे इससे पहले जेपी नड्डा की राष्ट्रीय टीम में भी उपाध्यक्ष थीं।

उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत को भाजपा एसटी मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में भाजपा की राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की दृष्टि से यह नियुक्ति महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राजस्थान सहित, आदिवासी बहुल राज्यों में पार्टी संगठन को मजबूत करने में रावत की भूमिका अहम हो सकती है।

राजस्थान भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेश मंगल को पीपूष गोयल के साथ राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं सुनील बंसल को राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी मिली है। इन नियुक्तियों के जरिए राजस्थान के संगठनात्मक अनुभव वाले नेताओं को केन्द्रीय संगठन में जगह दी गई है।

नई राष्ट्रीय टीम में राजस्थान भाजपा प्रभारी राधा मोहन दास अप्रवाल को स्थान नहीं मिला है। राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर भी राष्ट्रीय टीम में जगह नहीं बना सकीं। इसके बजाय राजेश (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

को यह दोहरी रणनीति सीजेपी के बाद की जैनरेशन जी की उभरती मुखरता को नियंत्रित कर पाएगी या नहीं, यह अभी एक खुला राजनीतिक सवाल है।

काँकरोच जन्ता पार्टी के जैनरेशन ज़ैड आंदोलन, जिसने पेपर लोक के खिलाफ प्रदर्शनों के बाद तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया था, उससे जुड़े छात्र संगठनों ने प्रधानमंत्री के भाषण को इस बात के एक और प्रमाण के रूप में लिया है कि सरकार युवाओं के गुस्से को समझने और उसके मुलू का कारणों को दूर करने के बजाय उसे किसी लेबल से जोड़ने में अधिक सहज है।

सीजेपी और वामपंथी छात्र संगठनों को पहले ही अर्बन नक्सल जैसे आरोपों का सामना करना पड़ा है। अब इस्तेमाल किया गया नया शब्द उस रणनीति के विस्तार के रूप में देखा जा रहा है, जिसे ऐसी पीढ़ी के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

शहजाद पूनावाला ने भाजपा के सभी पदों से इस्तीफा दिया

- उन्होंने भाजपा व शीर्ष नेतृत्व को मार्ग दर्शन व सहयोग के लिये आभार व्यक्त किया।

कर लिया जाए। इससे पहले भी उन्होंने 30 जुलाई को इस्तीफा दिया था, लेकिन पार्टी ने उसे स्वीकार नहीं किया था। सोमवार को भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने एकस पर जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने एक बार फिर अपना इस्तीफा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को भेजा है और इसे स्वीकार करने का अनुरोध किया है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)



सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार



श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री



श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री

जल प्रबंधन में नए कीर्तिमान जल समृद्ध हो रहा राजस्थान

₹91,000 करोड़ की लागत से राम जल सेतु लिंक परियोजना

संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना

- 4.98 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा
- 17 जिलों को पेयजल-
जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, अजमेर, ब्यावर, डीग कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, धौलपुर



₹34,102 करोड़ की यमुना जल परियोजना

शेखावाटी को वर्षों बाद जल

32 वर्षों का इंतजार पूरा

चूरु, सीकर, झुंझुनू – भरपूर पानी



राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल समझौते (MoA) पर हस्ताक्षर

गंग, भाखड़ा एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना के नहरी-तंत्र के जीर्णोद्धार एवं सुदृढीकरण के लिए राशि ₹5500 करोड़

लाभान्वित जिले - हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चुरु, बीकानेर, फलौदी

जैसलमेर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, डीडवाना- कुचामन, बाड़मेर और बालोतरा

ब्राह्मणी-राणा प्रताप सागर- बनास लिंक

680 एमसीएम जल बनास नदी में अपवर्तन लाभान्वित जिले भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर, अजमेर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, भरतपुर एवं डीग

₹2,500 करोड़

की अपर हाई लेवल कैनाल माही परियोजना से बांसवाड़ा के 338 गांवों में सिंचाई

देवास तृतीय एवं चतुर्थ बांध का निर्माण

राज्य सरकार द्वारा राजसमंद जिले में जल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु खारी फीडर की जल संवहन क्षमता को दोगुना करने की लगभग ₹150 करोड़ की महत्वाकांक्षी परियोजना

₹7,355 करोड़ की

परवन वृहद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना से कोटा, बारां, झालावाड़ के 571 गांवों में 2.01 लाख हेक्टेयर सिंचाई एवं 1402 गांवों में पेयजल सुविधा

पाली एवं सिरौही में पेयजल आपूर्ति हेतु सेई एवं साबरमती बांधों का निर्माण कर जवाई बांध में पानी पहुंचाया जाएगा। परियोजना लागत ₹1,255.90 करोड़ है साथ ही, सेई बांध की टनल क्षमता बढ़ाने पर ₹65 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं।

माही बेसिन के अनास एवं सोम नदियों के 500 MCM अधिशेष जल को जाखम बांध, जयसमंद बांध के साथ साथ सोम-कमला-अंबा बांध के माध्यम से जवाई बांध एवं जालौर तक आपवर्तित करने का संकल्प लाभान्वित जिले: बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूंबर, डूंगरपुर, उदयपुर, पाली, जालौर एवं जोधपुर

विचार बिन्दु

महान ध्येय का मौन में ही सृजन होता है। –साने गुरुजी

क्या सत्ताधीशों का काम केवल विरोध को कुचलने का रह गया है?

दिनांक 13 अगस्त, 2026 को बार कौंसिल ऑफ इंडिया (बी सी आई) के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने आदेश जारी किया कि हैदराबाद के विधि विश्वविद्यालय, NALSAR के 2026 बैच के छात्रों का पंजीयन किसी राज्य की बार कौंसिल में नहीं किया जाएगा। बिना बार कौंसिल में रेजिस्ट्रेशन के कोई विधि स्नातक किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। उल्लेखनीय है कि NALSAR के छात्रों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को दीक्षांत समारोह में बुलाने का विरोध किया था और कहा था कि वे उनके हाथों से डिग्री नहीं लेंगे। इसका कारण यह बताया गया कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत देश के छात्रों की अभिव्यक्ति के अधिकार की रक्षा करने में असमर्थ रहे हैं। जब दिल्ली में पुलिस अत्याचार के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई तो मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि उनके पास ये चीडियो देखने के लिए समय नहीं है। यह बयान युवाओं के प्रति उनकी असंवेदनशीलता दर्शाता था। उनके फैसले, युवाओं के हित के विपरीत रहे हैं। पाठकों के लिए यह जानना उचित होगा कि पारंपरिक रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश को NALSAR के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि की तरह बुलाया जाता रहा है।

बार काउंसिल के अध्यक्ष मनन मिश्रा वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कांग्रेस के टिकट पर बिहार से विधायक का चुनाव लड़ा। बाद में 2013 में ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और भाजपा के प्रति स्वामी भक्ति दिखाने के कारण इनको राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया ये 2014 से लगातार बार काउंसिल के अध्यक्ष बने हुए हैं। मिश्रा के इस मननमाने और बेतुके आदेश की सब वक्तों, नेताओं, यहां तक कि भाजपा के नेताओं ने भी कड़ी निंदा की। काँकरोच जनता पार्टी, (सी जे पी) के नेताओं ने तो यहां तक घोषणा कर दी कि वे मनन मिश्रा के सरकारी आवास और उनके कार्यालय का घेराव करेंगे। तीव्र विरोध को देखते हुए मनन मिश्रा को दो घंटों में ही अपना वया आदेश वापस लेना पड़ा। उन्होंने बड़े भोलेपन से मीडिया के माध्यम से यह बयान दिया कि वे युवाओं के भविष्य को किसी प्रकार से खराब नहीं करना चाहते हैं ।

मनन मिश्रा का यह आदेश तो केवल एक उदाहरण है, वास्तविकता तो यह है कि सत्ता की कुर्सी पर बैठा हर व्यक्ति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुंठित करने का कार्य कर रहा है। विरोध के प्रति इतनी असहिष्णुता पहले नहीं देखी गई। नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी, संविधान द्वारा दी गई है । जहां, जिसको अवसर मिलता है वह विरोध को सहन नहीं कर पाता और उसके स्वर को कुचलने का प्रयास करने लगता है।

देश के कई प्रमुख विश्वविद्यालयों में 15–20 साल से छात्र संगठन के चुनाव नहीं हुए हैं। अपनी राजनीतिक विचारधारा को अभिव्यक्त करने का कोई मंच ही छात्रों को उपलब्ध नहीं है। केंद्र एवं राज्यों में सरकारों ने अपने चहेते कुलपति और अध्यक्ष सभी शिक्षण संस्थाओं में बिठा दिए, ताकि छात्रों को उनकी ही विचारधारा को मानने हेतु बाध्य किया जा सके। सरकार विरोधी विचारधारा रखने वाले लोगों को टारगेट करके प्रताड़ित करने का प्रयास किया जाता है ।

हाल ही में काँकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान कई विश्वविद्यालयों और संस्थाओं ने इस आंदोलन में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया और छात्रों को सलाह दी कि इसमें भाग न लें। यह धमकी तक दी गई कि यदि उन्होंने इसमें भाग लिया तो उन्हें विश्वविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है। एक विश्वविद्यालय ने तो यहां तक लिख दिया कि यदि उनके विश्वविद्यालय के छात्र आंदोलन में भाग लेंगे तो, विश्वविद्यालय और केंद्र सरकार के संबंध पर विपरीत भाव पड सकता है। ऐसे आदेश निकालने वालों में दिल्ली विश्वविद्यालय, जे एन यू, जामिया मिलिया, आई आई टी खडकी और मद्रास जैसे प्रतिष्ठित संस्थान भी शामिल हैं। विश्वविद्यालय एवं शैक्षिक संस्थानों का कार्य स्वतंत्र सोच को विकसित करने का है अथवा उसे दबाने का? यदि विश्विद्यालय, सरकार विरोधी विचारधारा के स्वर को दबाने का काम करेंगे तो उन्हें विश्वविद्यालय कहना बेमानी होगा। विश्वविद्यालय छात्र संघों से निकले कई छात्र नेता, बाद में राष्ट्रीय राजनीति में आए और विधायक, सांसद और मंत्री तक बने, जैसे अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, रवि शंकर प्रसाद आदि आदि।

यह देश का दुर्भाग्य ही है कि जिस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी संविधान में दी गई है, उसे ही किसी न किसी तरह से, हर स्तर पर दबाने का प्रयास किया जा रहा है। यह काम सरकारी विभागों के अधिकारी तो करते ही थे, अब तो उच्च शिक्षण संस्थान तक यही करने लगे हैं। कई बार तो लगता है कि प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के मुखिया के रूप में नियुक्त होने के

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलने का काम केवल वर्तमान भाजपा सरकार ही नहीं कर रही है । पूर्व में भी, हर सत्ताधारी दल ने अपने विरोधियों की आवाज़ को दबाने और कुचलने का ही काम किया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो आपातकाल के रूप में 1975 में सामने आया, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूरे देश में आपातकाल लगा दिया था।

प्रतिबंध लगा दिया गया । आपात काल के बाद मार्च, 1977 में जब चुनाव हुए, तब जनता ने दिखा दिया कि वह अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहती है और जो भी उसे दबाने का प्रयास करेगा, उसे इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। जनता ने इंदिरा गांधी जैसी शक्तिशाली प्रधानमंत्री की सरकार को 1977 के चुनावों में बुरी तरह पराजित करके सत्ता से उखाड़ फेंका।

गत कुछ वर्षों से जिस प्रकार की असहिष्णुता, विचारों की भिन्नता के लिए और सत्ताधारी दल के मत से अलग मत रखने वालीयों के प्रति दिखाई जा रही है, उससे तो यही लगता है कि राजनैतिक दलों ने इतिहास से कुछ नहीं सीखा और फिर वही गलती दोहरा रहे हैं। इस भय के वातावरण के कारण सरकार के विरुद्ध मुँह खोलना, जोखिम भरा काम हो गया है। जिन विद्यार्थियों ने काँकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर के प्रदर्शन में भाग लिया, पुलिस द्वारा उनकी पहचान कर उनके विरुद्ध कार्रवाई कार्यवाही की जा रही है।

आजकल तो विश्वविद्यालय में कुलपति, प्रोफेसर एवं शिक्षकों के पदों पर चयन हेतु, सत्ताधारी दल की विचारधारा वाला व्यक्ति होना, अनिवार्य शर्त बन गई है। यहां तक कि निजी विश्वविद्यालय में भी यदि सरकार के निर्णय के विरुद्ध कोई आवाज उठा दें, तो वहां के मुखिया को उनके मालिकों के माध्यम से हटाने की कार्यवाही की जाती है।

मीडिया अपनी सही भूमिका तभी निभा सकता है जब वह अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखे और निष्पक्ष रहे । कुछ वर्षों से यह देखा गया है कि मीडिया अंग्रेजी की कहावत “ more loyal than the king” को सही सिद्ध करने में लगा है। यह मीडिया निष्पक्षता की सभी सीमाओं को लांघते हुए सत्ताधारी दल को खुश करने में लगा है। इस प्रकार के मीडिया को ‘गोदी मीडिया’ की संज्ञा दी गई है यानि सरकारी की गोद में बैठा मीडिया। इनका उद्देश्य स्पष्ट है, सरकार के अधिकाधिक विज्ञापन उन्हें मिलते रहें और सरकार का पूर्ण संरक्षण उन्हें प्राप्त हो।

आज, यदि धरातल के वास्तविक समाचार लोगों तक पहुंच रहे हैं तो, वह केवल सोशल मीडिया की बलते वन है। कुछ साहसी पत्रकार, फील्ड में जाकर वास्तविकता उजागर करने का प्रयास करते हैं कि उनके लिए भी जोखिम बहुत बढी है । सरकार के किसी निर्णय और कार्रवाई का विरोध, उनके लिए कितना भारी पड़ सकता है, इसके अनेक उदाहरण गत कुछ वर्षों में देखने में आए हैं । कई चैनल बंद कर दिए गए या उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कुछ के विरुद्ध ई डी, सी बी आई, इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों को छोड़ दिया गया है।

सरकार विरोधी रिपोर्टिंग करने वाले कुछ पत्रकारों को गिरफ्तार तक कर लिया गया । यूपी में एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील में पानी और नमक के साथ रोटी खाते हुए बच्चों को दिखा दिया तो सरकार ने उस पत्रकार को गिरफ्तार करवा दिया। जिस पत्रकार ने हाथरस बलात्कार और हत्या कांड के सच को मीडिया में प्रसारित करने की कोशिश की तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया । उसकी जमानत भी सुप्रीम कोर्ट के दखल से हुई।

कोई शायर या कर्मेडियन ऐसी कोई बात सार्वजनिक मंच से कह दे जो सरकार को अपने विरोध में दिखाई दे तो उस पर कार्रवाई करने में कोई देरी नहीं होती। सरकार के इस काम में, दुर्भाग्य से, प्रशासन भी पूरी तरह सहयोग करने के लिए, हर गैर कानूनी आदेश का पालन करने के लिए तत्पर रहता है । उदाहरणार्थ, लद्दाख के जिला प्रशासन ने बिना पर्याप्त कारण के, सोनम वांगचुक को नेशनल सिक्वोरिटी एक्ट में गिरफ्तार करके सात महीने के लिए जेल में डाल दिया था। बाद में, स्वयं गृह मंत्रालय को एन एच के अंतर्गत जारी आदेश को वापस लेना पड़ा । इससे, सरकार की बड़ी किरकिरी हुई थी ।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने में जहां सत्ता पक्ष के नेताओं की प्रमुख भूमिका है, वहीं, संविधान की शपथ लेने वाले नौकरशाहों और अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों की भी उत्तनी ही भूमिका है । यदि वे अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी रखें तो सरकार, चाहेतु हुए भी असंवैधानिक तरीके नहीं अपना सकती है। बस, इसके लिए उनको स्वयं को दो ही बातों से मुक्त करना होगा – भय और लोभ। अधिकारी गण, सरकार के उचित –अनुचित सभी आदेशों का पालन केवल इसलिए करते हैं कि उन्हें मनमाना पोस्टिंग मिल जाए या वह नेताओं के साथ मिलकर अनेकित रूप से धन कमा सके, या फिर वे इतने कायर है कि उनके विरुद्ध प्रताड़ना की कार्यवाही से भय खाते हैं। यदि अधिकारी अपने विवेक से कानून सम्मत काम करते तो जंतर मंतर के प्रदर्शनकारी छात्रों पर प्लेटेड गन का इस्तेमाल नहीं होता और बिहार में कोई सिपाही एके–47, प्रदर्शनकारियों पर नहीं तान देता।

ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति कुर्सी पर बैठे, उसका पहला काम ही विरोध के स्वर को दबाने का हो जाता है। यह प्रवृत्ति अब शायद जनता के दबाव से कम होगी और अधिकांरीगण, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कार्य करेंगे। राजनेताओं को सबक सिखाने का काम तो जनता, केवल चुनाव के माध्यम से पांच साल में एक बार कर सकती है। राजनीतिज्ञों को यह बात समझती होगी कि जनता के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करके वे न केवल लोकतंत्र की रक्षा कर पाएंगे अपितु स्वयं की छवि और भविष्य को भी बेहतर बना पाएंगे। अन्यथा, मौका लगने पर जनता उन्हें कैसे पटखनी दे देती है, इसका इतिहास गवाह है ।

–अतिथि सम्पादक,

राजेन्द्र भागवान

(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)



मदन सिंह काला

संविधान की प्रस्तावना हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। 26 जनवरी 1950 को जब यह लागू हुआ, तो हर भारतीय नागरिक से चार वादे किए – न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। 75 वर्ष बाद आज हमें यह परखना है कि इन वादों को जमीन पर उतारने में हम कहां तक सफल हुए। यदि प्रस्तावना एक संकल्प है, तो आरक्षण उस संकल्प को पूरा करने का सबसे बड़ा संवैधानिक उपकरण है।

इतिहास हमें बताता है कि भारत की हार का सबसे बड़ा कारण बाहरी आक्रांता नहीं, बल्कि अंदर की फूट थी। इस फूट की जड़ जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था में थी। समाज को चार हिस्सों में बांट दिया गया। ब्राह्मण को समस्त समाज को शिक्षा देने का दायित्व मिला, पर उसने उसे सीमित रखा। क्षत्रय को रक्षा की जिम्मेदारी मिली, पर वह अकेला बार–बार हारता गया क्योंकि उसके पीछे पूरा समाज नहीं खड़ा था। वैश्य का काम शुद्ध व्यापार था, पर उसने उसे ईमानदारी से नहीं निभाया गया। शूद्रों को खेती, पशुपालन, भवन निर्माण, कपड़ा बुनाई, लोहे–सोने का काम, जूते बनाने जैसे सभी तकनीकि व उत्पादकता जैसे कार्यों में लगा दिया गया, लेकिन उन्हें शिक्षा और संपत्ति के अधिकार से वंचित रखा गया। अतिशूद्रों को तो “पूर्व जन्म के कर्मों” का हवाला देकर अछूत घोषित कर समाज से बिल्कुल अलग कर दिया गया।

इस तरह समाज की 80–85 प्रतिशत शक्ति को शिक्षा, सम्मान और

अवसरों से दूर रख दिया गया। नतीजा यह हुआ कि देश न आर्थिक रूप से मजबूत बन पाया, न सैन्य रूप से और न बौद्धिक रूप से। यही कारण है कि हम बार–बार गुलाम हुए।

इसी ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए संविधान निर्माताओं ने ‘सकारात्मक कार्रवाई’ का मार्ग चुना। यह कोई राजनीतिक चाल या दया नहीं थी, बल्कि एक संवैधानिक उपचार था। यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि संविधान में आरक्षण का आधार कभी आर्थिक कमजोरी नहीं रहा। संविधान सभी में बहस के दौरान डॉ. बाबासाहब आंबेडकर ने स्पष्ट कहा था – “I don't prefer the competent government, I prefer the representative government.” इसका अर्थ है आरक्षण का उद्देश्य ‘योग्य सरकार’ नहीं, बल्कि ‘प्रतिनिधि सरकार’ बनाना है। इसलिए अनुच्छेद 16(4) में आधार ‘सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन’ रखा गया है। दुनिया के अन्य देशों में भार Affirmative Action है, लेकिन उसका आधार भी आर्थिक नहीं, बल्कि ऐतिहासिक भेदभाव और कम प्रतिनिधित्व है।

–आरक्षण प्रतिभा के विरुद्ध व्यवस्था नहीं है; यह उस असमान प्रारंभिक स्थिति को संतुलित करने का संवैधानिक प्रयास है जिसमें सभी प्रतियोगियों को समान अवसर कागज पर तो मिलता है, लेकिन सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक परिस्थितियाँ समान नहीं होतीं।–जिस बच्चे के घर में किताब नहीं, कोचिंग नहीं, अच्छे स्कूल नहीं, उसे उसी लाइन से दौड़ाना जहाँ दूसरे के पास पीढ़ियों से संसाधन हैं, यह समझना नहीं होगा। आरक्षण उसी दौड़ को बराबर करने के लिए ‘हैंडीकेप’ की तरह है। एक बार बराबरी आ जाए, फिर मैदान सबके लिए खुला है।

75 वर्षों का परिणाम सामने है। एससी/एसटी की साक्षरता 1951 के 10 प्रतिशत से बढ़कर 2021 में 70 प्रतिशत से अधिक हो गई। आज इन वर्गों से आईएएस, आईपीएस, वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी, उद्यमी और जनप्रतिनिधि निकल रहे हैं। राज्यों में आरक्षण की स्थिति अलग–अलग है। सिक्किम में कुल 85 प्रतिशत आरक्षण है, तमिलनाडु में 69 प्रतिशत, राजस्थान में 64 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 60 प्रतिशत और कर्नाटक में 50 प्रतिशत की सीमा लागू है, जिसे राज्य सरकार ने 66 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा है। केंद्र में एससी 15 प्रतिशत, एसटी 7.5 प्रतिशत, ओबीसी 27 प्रतिशत और इडब्ल्यूएस 10 प्रतिशत आरक्षण लागू है।

आरक्षण के बाद भारत की तस्वीर बदली। आजादी के बाद हम कभी किसी विदेशी ताकत के गुलाम नहीं बने। हमारी तीनों सेनाएं – थल, नौसेना, वायुसेना – दुनिया की सबसे बहादुर सेनाओं में हैं।–ध्यान देने योग्य बात है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं की कॉम्बैट/लड़ाकू भर्ती में कोई जातिगत आरक्षण नहीं है।–वहां चयन पूरी तरह मेरिट, शारीरिक दक्षता और राष्ट्र भक्ति के आधार पर होता है, और यही हमारी ताकत है। इसी तरह ओलंपिक और एशियाड में भी कोई आरक्षण नहीं है, फिर भी एससी/एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के खिलाड़ी मिलकर मेडल लाते हैं। यह सिद्ध करता है कि अवसर मिलने पर हर वर्ग प्रतिभा दिखा सकता है।

पिछले वर्षों में ‘समरसता’ शब्द भाईचारे का प्रतीक बन चुका है। लेकिन यहां गंभीर आपत्ति है। डॉ. बाबासाहब आंबेडकर ने स्वयं कहा था – “I don't want Samrasta, I want Samata।” पूरे समरसता नहीं, समानता चाहिए। यदि ‘समरसता’ का अर्थ जन्म आधारित कर्म को स्वीकार करता है, तो यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है। संविधान का लक्ष्य ‘समरसता’ नहीं, बल्कि ‘समानता और बंधुत्व’ है। वास्तविक समरसता तभी होगी जब हर वर्ग का व्यक्ति मंदिर से लेकर प्रयोगशाला तक, खेत से लेकर संसद तक, अपनी योग्यता से आगे बढ़ सके।

सरकारी क्षेत्र में आरक्षण के बाद भी समाज के कुछ क्षेत्रों में असमानता बिकराये को लेकर कई बार राजनेताओं और जिला प्रशासन से आग्रह कर चुके हैं। अपनी समस्या से अवगत करवाया है और किराये को तर्कसंगत एवं सामान्य करने की मांग रखी है। लेकिन लगातार आग्रह के बावजूद यदि प्रशासन से आग्रह कर चुके हैं, फिर भी कोई निर्णय नहीं होता तो आखिर ये अपनी बात किसके सामने रखें? सरकारी भवन जनता के पैसों से बनते हैं। टाउन हॉल भी जनता की सांस्कृतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए है। उसका उद्देश्य केवल किराये से अधिकतम राज्यस्व अर्जित करना नहीं हो सकता। व्यावसायिक आयोजन और सांस्कृतिक आयोजन एक कैसे हो सकते हैं? जिला प्रशासन को एक महत्वपूर्ण अंतर समझना होगा व्यावसायिक कार्यक्रम और गैर-व्यावसायिक सांस्कृतिक आयोजन एक समान नहीं होते।

यदि कोई बड़ा व्यावसायिक कार्यक्रम है, किसी कंपनी का प्रचारत्मक आयोजन है अथवा ऐसा कार्यक्रम है जिससे आयोजक को आर्थिक लाभ होता है, तो उसके लिए अलग किराया निर्धारित किया जा सकता है। लेकिन स्थानीय रंगकर्मों जब अपनी जेब से या सीमित सद्योग से नाटक तैयार करते हैं, साहित्यकार साहित्यिक गोष्ठी आयोजित करता है या कोई सामाजिक संस्था जनजागरूकता का कार्यक्रम करती है, तो उनसे उसी किराये को लेकर कई बार राजनेताओं और जिला प्रशासन से आग्रह कर चुके हैं। अपनी समस्या से अवगत करवाया है और किराये को तर्कसंगत एवं सामान्य करने की मांग रखी है। लेकिन लगातार आग्रह के बावजूद यदि प्रशासन से आग्रह कर चुके हैं, फिर भी कोई निर्णय नहीं होता तो आखिर ये अपनी बात किसके सामने रखें? सरकारी भवन जनता के पैसों से बनते हैं। टाउन हॉल भी जनता की सांस्कृतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए है। उसका उद्देश्य केवल किराये से अधिकतम राज्यस्व अर्जित करना नहीं हो सकता। व्यावसायिक आयोजन और सांस्कृतिक आयोजन एक कैसे हो सकते हैं? जिला प्रशासन को एक महत्वपूर्ण अंतर समझना होगा व्यावसायिक कार्यक्रम और गैर-व्यावसायिक सांस्कृतिक आयोजन एक समान नहीं होते।

यदि कोई बड़ा व्यावसायिक कार्यक्रम है, किसी कंपनी का प्रचारत्मक आयोजन है अथवा ऐसा कार्यक्रम है जिससे आयोजक को आर्थिक लाभ होता है, तो उसके लिए अलग किराया निर्धारित किया जा सकता है। लेकिन स्थानीय रंगकर्मों जब अपनी जेब से या सीमित सद्योग से नाटक तैयार करते हैं, साहित्यकार साहित्यिक गोष्ठी आयोजित करता है या कोई सामाजिक संस्था जनजागरूकता का कार्यक्रम करती है, तो उनसे उसी

दिखती है। हिंदू धर्म जिसे सनातन धर्म भी कहा जाता है, के कई धार्मिक स्थलों, दुर्गों और पूजा से जुड़ी भूमिकाओं में आज भी पीढ़ीगत आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णों का वर्चस्व है। शूद्र और अतिशूद्र वर्ण की जातियों को व्यवस्थित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। इसी तरह देश के चार पीढ़ों के शंकराचार्यों और विभिन्न अखाड़ों के महामंडलेश्वरों जैसे शीर्ष पदों परंपरागत रूप से जन्म के आधार पर ही चयन होता आया है। जब तक धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं में सभी वर्गों को समान सम्मान और भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक ‘बंधुत्व’ अधूरा रहेगा।

इस संदर्भ में इडब्ल्यूएस आरक्षण का प्रश्न भी उठता है। 10 प्रतिशत इडब्ल्यूएस आरक्षण को संविधान की मूल भावना के विरुद्ध माना जा सकता है। सबसे बड़ी विसंगति यह है कि यह एससी/एसटी और ओबीसी के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों पर लागू ही नहीं होता यदि आधार आर्थिक है, तो फिर इन वर्गों के गरीबों को इससे बाहर क्यों रखा गया? इससे स्पष्ट है कि इसका आधार सामाजिक स्थिति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे बिना गहन बहस के स्वीकार कर लिया, लेकिन संवैधानिक दृष्टि से यह प्रावधान संदिग्ध है।

अब समय आ गया है कि हम आरक्षण को अंतिम लक्ष्य न मानें। – आरक्षण अंतिम लक्ष्य नहीं, बल्कि समान अवसर तक पहुंचने का साधन है। अंतिम लक्ष्य ऐसा समाज होना चाहिए जिसमें जन्म व्यक्ति की शिक्षा, सम्मान, रोजगार, नेतृत्व और जीवन की संभावनाओं को निर्धारित न करे। इसके लिए हमें एक संयुक्त मॉडल अपनाना होगा – आरक्षण + गुणवत्तापूर्ण शिक्षा + आर्थिक सशक्तिकरण + सामाजिक प्रतिनिधित्व + संवैधानिक बंधुत्व।

इसके लिए सबसे पहले हर 10 वर्ष में सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण होना चाहिए ताकि नीति सही आंकड़ों पर बने और ओबीसी के लिए ‘क्रीमी लेयर’ को सख्ती से लागू किया जाए। दूसरा बड़ा कदम शिक्षा में होना चाहिए। सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता,

–मदन सिंह काला, पूर्व आई.ए.एस अधिकारी

रंगमंच महंगा होगा तो अभिव्यक्ति सस्ती कैसे रहेगी?

दर पर किराया लेना न्यायसंगत नहीं है।

सरकार को चाहिए कि टाउन हॉल के किराये की अलग–अलग श्रेणियाँ निर्धारित करे। व्यावसायिक आयोजनों के लिए सामान्य दर हो, जबकि साहित्य, कला, रंगमंच, लोक संस्कृति, विद्यार्थी गतिविधियों और सामाजिक सरोकारों से जुड़े गैर–व्यावसायिक कार्यक्रमों के लिए अत्यंत रियायती दर रखी जाए। बीकानेर के रंगकर्मियों ने रवींद्र रंगमंच के लिए एक–दो वर्ष नहीं, बल्कि लगभग तीन दशक तक संघर्ष किया। अंतोद्वान किए, आवाज उठाई और सरकारों के सामने अपनी मांग रखी। लंबे संघर्ष के बाद रवींद्र रंगमंच बना। लेकिन आज स्थिति यह है कि उसका किराया भी सामान्य रंगकर्मों की आर्थिक पहुंच से बाहर होता जा रहा है। ऐसे में जिस मंच के लिए कलाकारों ने वर्षों संघर्ष किया, वही मंच यदि कलाकारों के लिए महंगा हो जाए तो यह व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। फिर भी टाउन हॉल की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह लंबे समय से बीकानेर की सांस्कृतिक गतिविधियों का सुलभ केंद्र रहा है। यदि टाउन हॉल भी कलाकारों की आर्थिक पहुंच से बाहर हो गया तो छोटे रंगकर्मियों और साहित्यिक–सांस्कृतिक संस्थाओं के पास आखिर कौन–सा विकल्प बचेगा?

सरकारें बड़े–बड़े सांस्कृतिक उत्सव आयोजित करती हैं। मंच सजते हैं, कलाकार बुलाए जाते हैं और संस्कृति के संरक्षण की बातें होती हैं। लेकिन संस्कृति का वास्तविक संरक्षण तब होगा, जब स्थानीय कलाकारों को वर्षभर मंच उपलब्ध होगा। बीकानेर के कलाकारों को किसी बड़े महोत्सव में

–राजेन्द्र जोशी, शिक्षाविद– साहित्यकार

मेघ	परिवार में आपसी सहयोग–सम्पन्न बना रहेगा, उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक खर्चों पर नियंत्रण रहे।
-----	---

वृष	मित्रों/रिश्तेदारों से चल रहे आपसी मतभेद दूर होने लगे। आज अस्त–व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। व्यावसायिक कार्यों एवं व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।
-----	--

मिथुन	परिवार में शुभ–मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में सुख–सुविधाओं में वृद्धि होगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।
-------	---

कर्क	घर–परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में अतिथियों के आमगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी।
------	--

सिंह	परिवार में मन को प्रसन करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों/रिश्तेदारों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। आज आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा।
------	---

कन्या	आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।
-------	--

तुला	व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। नौकरोंपेशा व्यक्तियों का प्रभाव–प्रभुत्व बढ़ेगा और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकेगी है। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।
------	--

वृश्चिक	व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। अटके हुए व्यावसायिक कार्य बनने लगेगे। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।
---------	---

धनु	आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। संभावित धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। घर–परिवार में अतिथियों का आमगम हो सकता है।
-----	--

मकर	व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। आज अटके हुए कार्य बनने लगेगे। चलते कार्यों में प्रगति होगी। आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है।
-----	--

कुंभ	नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आशासन प्राप्त होगी। अटके हुए कार्य बनने लगेगे। आज व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच–विचार हो सकता है। आज आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।
------	--

मीन	चंद्रमा अशुभ भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विनय हो सकता है। आज व्यक्तित्व पारिवारिक कार्यों के करण मानसिक तनाव रहेगा।
-----	---



राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
o/o मुख्य अभियंता (सिविल), एच.आई.सी. जीनदीप भवन, लालकोठी, जयपुर

निविदा आमंत्रण सूचना : TN-08 (RVU2627WSOB01112)

*आर.जी.टी.पी.पी.बी. रामगढ़ में कृषिगत टॉवर स्टेज-1 एवं 2 की आरसीसी संरचना का सुदृढीकरण और विद्युत मरम्मत कार्य हेतु ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा विवरण वेबसाइट <http://eproc.raajasthan.gov.in> (ई-निविदा हेतु), www.energy.raajasthan.gov.in/rvunl एवं www.sppp.raajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

राज.संवाद/सी/26/10025 RVUN/PR-4457 मुख्य अभियंता (Civil)

कार्यालय नगर परिषद, फलोदी जिला-फलौदी (राज0)

क्रमांक :-/न0प्रफ0/ 2026-27 / 3599 दिनांक :- 10.08.2026

:- ई-निविदा सूचना :-

नगर परिषद फलोदी द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिये उपयुक्त सक्षम श्रेणी में नियमानुसार उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 21.08.2026 को 12:00PM बजे तक ई-प्रोक्यूमेंट प्रक्रिया से वेबसाइट <https://eproc.raajasthan.gov.in> पर ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है, निविदा की विस्तृत जानकारी व वेब साइट <https://eproc.raajasthan.gov.in> व <https://sppp.raajasthan.gov.in> पर देखी व डाउनलोड कि जा सकती है।

TenderID :- 2026_DLB_585555_1, 2026_DLB_585555_2, 2026_DLB_585555_3
UBN No :- DLB2627WSOB17716, DLB2627WSOB17726, DLB2627WSOB17734
राज.संवाद/सी/26/10092 आयुक्त, नगर परिषद,फलोदी

कार्यालय नगर परिषद सुजानगढ़ (यूरू) राजस्थान

E-mail id:- nps222419@gmail.com Phone no. 01568-222419

क्रमांक :-न.प.स./विकास शाखा/ 2026 / 5556 दिनांक :- 10.08.2026

:-ई-निविदा सूचना-2026-27:-

नगर परिषद सुजानगढ़ द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिये उपयुक्त सक्षम श्रेणी के राज्य सरकार के विभागों में प्रजीकृत ठेकेदारों/ फर्मों से निविदा दिनांक 18.08.2026 तक आमन्त्रित की जाती है। निविदा प्रपत्रों को वेबसाइट <https://eproc.raajasthan.gov.in> से डाउनलोड कि जा सकता है एवं निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण वेबसाइट www.sppp.raj.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। निविदा का बीड क्रमांक (DLB2627WSOB17920), (DLB2627WSOB17923), (DLB2627WSOB17925), (DLB2627WSOB17892), (DLB2627WSOB17930) है। कार्यालय समय में किसी भी कार्य दिवस को नगर परिषद सुजानगढ़ के कार्यालय में एवं सूचना बोर्ड पर देखी जा सकती है।

आयुक्त
नगर परिषद, सुजानगढ़

राज.संवाद/सी/26/10123

कार्यालय नगर परिषद सुजानगढ़ (यूरू) राजस्थान

E-mail id:- nps222419@gmail.com Phone no. 01568-222419

क्रमांक :-न.प.स./विकास शाखा/ 2026 / 5546 दिनांक :- 10.08.2026

:-ई-निविदा सूचना-2026-27:-

नगर परिषद सुजानगढ़ द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिये उपयुक्त सक्षम श्रेणी के राज्य सरकार के विभागों में प्रजीकृत ठेकेदारों/ फर्मों से निविदा दिनांक 18.08.2026 तक आमन्त्रित की जाती है। निविदा प्रपत्रों को वेबसाइट <https://eproc.raajasthan.gov.in> से डाउनलोड कि जा सकता है एवं निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण वेबसाइट www.sppp.raj.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। निविदा का बीड क्रमांक (DLB2627WSOB17892) है। कार्यालय समय में किसी भी कार्य दिवस को नगर परिषद सुजानगढ़ के कार्यालय में एवं सूचना बोर्ड पर देखी जा सकती है।

आयुक्त
नगर परिषद, सुजानगढ़

राज.संवाद/सी/26/10122

भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर

क्रमांक :- लेखा/भ.वि.प्रा./2026-27/1213 - 26 दिनांक :- 13/08/2026

ऑनलाईन निविदा सूचना सं. 43/2026-27

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से भरतपुर विकास प्राधिकरण, में उपयुक्त श्रेणी एवं विभिन्न विभागों में ए एवं एच श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूमेंट प्रक्रिया से कुल 01 कार्य हेतु ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

उक्त कार्यों का विस्तृत विवरण, निविदा तर्ज, अनुमानित लागत राशि, निविदा वेचने, प्राप्त करने एवं खोलने की दिनांक आदि सम्पूर्ण विवरण वेबसाइट <http://eproc.raajasthan.gov.in>, www.urban.raajasthan.gov.in/utbharatpur एवं <http://sppp.raj.nic.in> portal पर देखा जा सकता है।

निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार का संयोग <http://eproc.raajasthan.gov.in> एवं <http://sppp.raj.nic.in> portal का अवलोकन करें।

UBN No.:- WAQ2627WLRC00114

अधीक्षणी अभियंता
भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर

राज.संवाद/सी/26/10042

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

उत्पादन वृत्त, रामगढ़ नगर, फलोदी-324001, फोन:- 0744-2327613

निविदा आमंत्रण सूचना

निम्नलिखित कार्यों / सामग्री की आपूर्ति / वार्षिक अनुबंध हेतु ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती है:-16 (RVU2627WSOB01094) संचालन एवं विपार अनुसूचन में सहानता तथा अधीक्षण अभियंता, जयपुरनगर (सिविल), राजकोटि प्रशासनिक बिक्रीनेर व क्र.सं.03 से 06 अधिशाषी अभियंता द्वितीय (सिविल), राजकोटि प्रशासनिक बिक्रीनेर व क्र.सं.07 से 09 अधिशाषी अभियंता (सिविल), राजकोटि प्रशासि लिंग हनुमानगढ व क्र.सं. 10 से 11 अधिशाषी अभियंता (सिविल), राजकोटि प्रशासि लिंग रत्नगढ के अन्तर्गत कार्यों हेतु प्रोक्यूमेंट प्रक्रिया हेतु ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। एवम् ई निविदा सूचना संख्या-13 (2026-27) के क्र.सं. 01 से 02 अधिशाषी अभियंता प्रथम (सिविल), राजकोटि प्रशासनिक बिक्रीनेर व क्र.सं. 02 अधिशाषी अभियंता - द्वितीय (सिविल), राजकोटि प्रशासनिक बिक्रीनेर के अन्तर्गत कार्यों हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाती है। इन कार्यों की अनुमानित लागत, निविदा शुल्क, निविदा बेचे जाने तथा खुलने की तारीख, धरोहर राशि व निविदा विशिष्टियां आदि का सम्पूर्ण विवरण वेबसाइट <http://eproc.raajasthan.gov.in> पर देखा जा सकता है।

UBN :- VPN2627WSOB01224,1225,1211, 1213, 1215,1216,1217,1218,1221,1214,1212 (NIT No.12)
UBN :- VPN2627WSOB01222,1219 (NIT No.13)

राज.संवाद/सी/26/10011 रा.रा.वि.प्र./TR-7751/2026 अधीक्षण अभियंता (सिविल), बीकानेर

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

अल्पकालिक निविदा सूचना संख्या-12 और 13 (2026-27)

केन्द्र / राज्य सरकार के विभागों एवं रा. वि. प्र. लि. के उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत / मान्य व अनुभवी निविदाकारों से अल्पकालिक निविदा सूचना संख्या- 12 (2026-27) के क्र.सं. 01 से 02 अधिशाषी अभियंता प्रथम (सिविल), राजकोटि प्रशासनिक बिक्रीनेर व क्र.सं.03 से 06 अधिशाषी अभियंता द्वितीय (सिविल), राजकोटि प्रशासनिक बिक्रीनेर व क्र.सं.07 से 09 अधिशाषी अभियंता (सिविल), राजकोटि प्रशासि लिंग हनुमानगढ व क्र.सं. 10 से 11 अधिशाषी अभियंता (सिविल), राजकोटि प्रशासि लिंग रत्नगढ के अन्तर्गत कार्यों हेतु प्रोक्यूमेंट प्रक्रिया हेतु ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। एवम् ई निविदा सूचना संख्या-13 (2026-27) के क्र.सं. 01 से 02 अधिशाषी अभियंता प्रथम (सिविल), राजकोटि प्रशासनिक बिक्रीनेर व क्र.सं. 02 अधिशाषी अभियंता - द्वितीय (सिविल), राजकोटि प्रशासनिक बिक्रीनेर के अन्तर्गत कार्यों हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाती है। इन कार्यों की अनुमानित लागत, निविदा शुल्क, निविदा बेचे जाने तथा खुलने की तारीख, धरोहर राशि व निविदा विशिष्टियां आदि का सम्पूर्ण विवरण वेबसाइट <http://eproc.raajasthan.gov.in>, <http://sppp.raajasthan.nic.in>, & www.rvvpn.co.in पर देखा जा सकता है।

UBN :- VPN2627WSOB01224,1225,1211, 1213, 1215,1216,1217,1218,1221,1214,1212 (NIT No.12)
UBN :- VPN2627WSOB01222,1219 (NIT No.13)

राज.संवाद/सी/26/10011 रा.रा.वि.प्र./TR-7751/2026 अधीक्षण अभियंता (सिविल), बीकानेर

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

संगलपुरा, जयपुर रोड, बीकानेर - 334001 दूरभाष : 0151-2226200

अल्पकालिक ई - निविदा सूचना

"132 केबी जीएस. एवं डल्टरस से भोजपुर, गणेशसर-सुमेरिया, सावर एवं तोलासर-रोलासर फीडर्स द्वारा क्रमशः 33/11 केबी S/M योगाणी जोहड़ी, गणेशसर-सुमेरिया, सावर तथा तोलासर-रोलासर के इंटरकनेक्शन (I/C) हेतु एस.टी.पी. (STP) योजना के अंतर्गत A.C.S.R. (0.2g) कंडक्टर सहित 33 केबी ओवरहेड सिंगल सर्किट लाइन (लंबाई क्रमशः 16.00 कि.मी. + 0.27 कि.मी. + 0.25 कि.मी. + 3.50 कि.मी. = कुल 20.02 Kms.) के निर्माण कार्य को श्रम दर (Labour Rate Basis) पर निष्पादित किए जाने हेतु सहायक अभियंता (एच एड एम), भागीपुरा उपखण्ड, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट, कुरू वृत्त द्वारा ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।"

TN- BZ- 05/2026-27(UBN No. JVV2627WSOB00371)

अन्य विवरण जैसे निविदा मूल्य, धरोहर राशि, निविदा प्रस्तुत करने / खुलने की तिथि का विवरण इत्यादि वेबसाइट www.energy.raajasthan.gov.in/jdvnl एवं www.eproc.raajasthan.gov.in द्वारा जानी जा सकती है। निविदाकर्ताओं को उनके स्वयं के हित में सहायता दी जाती है की ऑन लाइन www.eproc.raajasthan.gov.in पर निविदा डालने से पहले निविदा दस्तावेजों का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर ही। भूविषय में दून निविदाओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार के संशोधन तिथि बढ़ने की जानकारी आदि केवल वेबसाइट www.energy.raajasthan.gov.in/jdvnl, www.sppp.raajasthan.gov.in एवं www.eproc.raajasthan.gov.in पर उपलब्ध करायी जायेगी।

मुख्य अभियंता (जी.एम.)
जोधपुर डिस्ट्रिक्ट बीकानेर

राज.संवाद/सी/26/10030

राजस्थान सरकार

कार्यालय अतिथिशापी अभियंता चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

राजकीय जन्मान चिकित्सालय परिसर, मेरी हाथ बाग भरतपुर 321 001 (राज.)
eemhbharatpur@gmail.com, ee-nh-bharatpur@gov.in, Mob. 9983296632

क्रमांक/M&H/2026-27/5653 दिनांक : 13.08.2026

निविदा सूचना संख्या: 16/2026-27

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत विभिन्न कार्य जिला भरतपुर / डीएम / करौली में रु. 135.00 लाख के निर्माण कार्य हेतु राजस्थान सरकार के समक्ष उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राज्य सरकार / केन्द्र सरकार के अधिकृत संचालकों / केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग / डाटा एवं दूर संचार विभाग / रेलवे इत्यादि में सचिकृत जातीय हेतु पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के उपयुक्त श्रेणी के संवेदकों के समक्ष हों, से निम्नलिखित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूमेंट निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा से सम्बन्धित विवरण निम्न DIPRC की वेब साइट www.dipronline.org, <http://eproc.raajasthan.gov.in> व विभागीय वेब साइट <http://rajswasthya.nic.in> पर देखा जा सकता है।

अनुमानित लागत (रु.लाखों में) UBNNo.

NIB Code:-MHS2627A2533 UBN:is

Construction work of PHC Building 135.00 MHS2627WSOB03518

Bookna Distt Karauli 135.00 MHS2627WSOB03518

(संदीप वर्मा)
अतिथिशापी अभियंता
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, भरतपुर

DIPRC/14940/2026

परिवार की मौजूदगी में घर से 13 लाख का सोना और नगदी चोरी

चोरों ने परिवार वालों को कमरे में बंद कर लॉक लगा दिया और सीसीटीवी कैमरे बंद कर वारदात अंजाम दी

जोधपुर, (कासं)। शहर के बीजेएस कॉलोनी, हनुवंत ए सेक्टर में 14 अगस्त की आधी रात में चोरी हो गई। चोरों ने परिवार के लोगों को कमरे बंद कर बाहर से लॉक लगा दिया और सीसीटीवी कैमरे भी बंद कर डाले। बाद में घर से 12 लाख का सोना, एक लाख की नगदी आदि सामान चोरी कर ले गए। इस बारे में सूचना दिए जाने पर महामंदिर पुलिस ने मौके पर पहुंच चुकसाना किया। अब रास्तों पर लगे सीसीटीवी फुटेज से चोरों की पहचान के साथ तलाश की जा रही है। बीजेएस कॉलोनी, मटकी चौराहा

- पीड़ित ने अपने पूर्व नौकर बबलू, निवासी लखनऊ, पर शक जताया, एफआईआर में पुलिस ने उसे सदिग्ध के रूप में दर्ज किया

निवासी अक्षय ज्योत रतनू पुत्र भंवरदान रतनू ने रिपोर्ट दी है। इसके अनुसार 14 अगस्त की रात को

परिवार के सो जाने के बाद तीन अज्ञात व्यक्ति छत के रास्ते मकान में दाखिल हुए। बदमाशों ने उनके माता-पिता के कमरे से टेबल पर रखे सोने के आभूषण चुरा लिए। इनमें सोने की चेन, अंगूठी, मूर्ति और हाथों के कड़े सहित करीब 7-8 तोला सोना था। इसके अलावा करीब एक लाख रुपए नकद भी ले गए।

चोरों ने परिवारी अक्षय ज्योत और उनकी भाभी के कमरों को बाहर से लॉक कर दिया। घर में सामान अस्त-व्यस्त करने के साथ नौकर के ईयरफोन और 300 रुपए भी चोरी

किए। शिकायत में बताया गया कि बदमाशों ने घर के सभी सीसीटीवी कैमरे भी बंद कर दिए थे।

घटना के बाद अभय कमांड सेंटर में रूट के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। इसमें एक आई-20 कार के बी रोड पर गली नंबर 3 के पास रुकने और उसमें से तीन लोगों के उतरने की जानकारी सामने आई है। अक्षय ने अपने पूर्व नौकर बबलू, निवासी लखनऊ, पर शक जताया है। हालांकि एफआईआर में पुलिस ने उसे सदिग्ध के रूप में दर्ज किया है, उसकी सलिपता की पुष्टि जांच के बाद ही होगी।

आकाश कोचिंग ने सबसे बड़ा टैलेंट हंट “एग्जाम एंथे” लॉन्च किया

कोटा, (निसं)। आकाश कोचिंग ने सबसे बड़ा टैलेंट हंट एग्जाम एंथे (आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम) लॉन्च किया है। भारत की सबसे लंबे समय से आयोजित की जा रही इस टैलेंट आइडेंटिफिकेशन परीक्षा ने पिछले 16 वर्षों में 1 करोड़ से अधिक छात्रों

- भारत की सबसे लंबे समय से आयोजित की जा रही इस टैलेंट आइडेंटिफिकेशन परीक्षा ने 16 वर्षों में 1 करोड़ से अधिक छात्रों की भागीदारी दर्ज की है

की भागीदारी दर्ज की है। यह परीक्षा वैज्ञानिक मूल्यांकन, राष्ट्रीय स्तर की बेंचमार्किंग और पर्सनलाइज्ड अकादमिक इन्साइड्स के माध्यम से छात्रों को यह समझने में मदद करती है कि उन्हें किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है और आगे क्या करना है। छात्रों की योग्यता और प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने के लिए 100 प्रतिशत तक स्कॉलरशिप और 2.5 करोड़ रुपए के कैश प्राइज दिए जाएंगे।

आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम (एंथे) पिछले 16 वर्षों से तैयारी और छात्रों की सेल्फ-अवेयरनेस के बीच इसी गैप को दूर करने की दिशा में काम कर रहा है। इस शुरुआती आकलन का महत्व उन छात्रों की समझता की यात्राओं से भी स्पष्ट होता है, जिन्होंने आगे चलकर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन किया। नीट 2026 में टॉप 100 में रैंक हासिल करने वाले आकाश के 41 छात्रों में से 31 छात्र पहले एंथे में क्वालीफाई कर चुके थे। इसी तरह जेईई एडवांस 2026 के टॉप 100 में जगह बनाने वाले 11 छात्रों में से 7 छात्र एंथे से जुड़े रहे हैं। ये उपलब्धियां बताती हैं कि छात्र की शुरुआती

कोटा में आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम के पोस्टर का विमोचन किया गया।

पहचान, व्यवस्थित अकादमिक तैयारी और लगातार मार्गदर्शन उसकी प्रतियोगी परीक्षा की पूरी यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

एंथे के महत्व पर बात करते हुए आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड (एईएसएल) के एमडी एवं सीईओ चंद्र शेखर गरिसा रेड्डी ने कहा कि हमारे लिए एंथे कभी भी सिर्फ ऐसी परीक्षा नहीं रही है, जो किसी छात्र की स्कॉलरशिप तय करती हो। इसका बड़ा उद्देश्य छात्रों को अपनी अकादमिक क्षमता को समझने में मदद करना है, खासकर उस स्तर पर जब सही मार्गदर्शन उनके भविष्य में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। हमारा प्रयास है कि हर छात्र एंथे के बाद अपनी अकादमिक यात्रा को लेकर ज्यादा स्पष्टता और आगे बढ़ने के लिए बेहतर समझ के साथ आगे बढ़े। एंथे में शामिल होने वाले हर छात्र को एक विस्तृत 'एंथे इंटेलेजेंस रिपोर्ट' दी जाती है, जिसे परीक्षा के प्रदर्शन

को उपयोगी और व्यावहारिक अकादमिक इन्साइड्स में बदलने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। यह रिपोर्ट छात्रों को विषयवार अपनी मजबूतियों और उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करती है, जिन पर उन्हें अधिक ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही, यह उन्हें यह समझने का नजरिया भी देती है कि वे प्रतियोगी परीक्षाओं की चुनौतियों का सामना करने के लिए किनसे तैयार हैं। यह परीक्षा कक्षा से तक के छात्रों के लिए खुली है और ऑनलाइन व ऑफलाइन, दोनों माध्यमों में आयोजित की जाएगी। एंथे 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन अब शुरू हो चुके हैं और छात्र आधिकारिक एंथे पोर्टल तथा देशभर में मौजूद आकाश सेंटर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा 27 अक्टूबर से 1 नवंबर 2026 तक आयोजित होगी, जबकि ऑफलाइन परीक्षा 11 अक्टूबर, 25 अक्टूबर और 1 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी।

तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक को मारी टक्कर, युवक की मौत

- दूसरा युवक गंभीर घायल, हालत गंभीर होने पर जयपुर रैफर किया
- मंदिर में जागरण कार्यक्रम में जा रहे थे, हादसे के बाद वाहन चालक फरार

बाइक सवार कृष्ण कुमार और देवराज सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा देखकर मौके पर पहुंचे राहगीरों ने दोनों घायलों को तत्काल राजकीय उप जिला अस्पताल, खेतड़ी पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद कृष्ण कुमार को मृत घोषित कर दिया। वहीं देवराज की हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे जयपुर रैफर कर दिया गया।

ग्रामीणों के अनुसार कृष्ण कुमार और देवराज अपने साथियों के साथ ग्रामीणों के सहयोग से पिछले करीब तीन वर्षों से शिव मंदिर में जागरण कार्यक्रम आयोजित आ रहे थे। दोनों युवकों के साथ हुए हादसे की सूचना मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर

दौड़ गई। मृतक कृष्ण कुमार विवाहित था और उसका करीब एक साल का बेटा है। वह जयपुर में मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था। कृष्ण कुमार के बड़े भाई सुनील और पिता जगदीश भी मजदूरी करते हैं। वहीं घायल देवराज अविवाहित है और निजामपुर मोड़ पर वेल्टिंग का काम करता है। हादसे की सूचना मिलते ही खेतड़ीनगर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पुलिस ने दुर्घटना से संबंधित जानकारी जुटाई। टक्कर मारने वाली गाड़ी मौके से फरार हो जाने के कारण पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। एएसआई विजय कुमार ने बताया कि हादसे के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है।

बारिश के पानी से भरे गड्ढे में डूबने से दो बच्चों की मौत

जोधपुर, (कासं)। शहर के निकटवर्ती करवड़ क्षेत्र में आई जेडी कॉलोनी में भरे बारिश के पानी में बने गड्ढे में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई। रविवार को बच्चे खेलते समय पानी तक पहुंच गए, बाद में आठ-दस फीट बने गड्ढे तक उतर गए और दलदल में फंसने से उनकी मौत हो गई। बच्चे समय पर घर नहीं पहुंचे तो परिजनों को चिंता हुई। उन्होंने अपने स्तर पर बच्चों को इधर-उधर ढूंढा, मगर वे नहीं मिले। रातभर बच्चों की तलाश की गई। सोमवार सुबह उनके शव पानी में ऊपर आने पर दिखे। दोपहर में पुलिस ने कारवाई की और पोस्टमार्टम करवा शव परिजन को सुपुर्द किए।

करवड़ थाना अधिकारी परमेश्वरी ने बताया कि मृतकों की पहचान विष्णु पटेल (13) पुत्र सोहनराय और नीतेश (11) पुत्र ओमराम निवासी लोरड़ी पंडितजी के रूप में हुई है। दोनों रविवार को घर से क्रिकेट खेलने के लिए निकले

- दोनों बच्चे रविवार को घर से क्रिकेट खेलने को निकले थे, दूसरे दिन शव मिले
- चिकनी मिट्टी होने के कारण प्रारंभिक तौर पर पैर फिसलने से पानी में गिरने की आशंका जताई

थे। देर रात तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। सोमवार सुबह दोनों के शव गांव के रमशान के पास जेडीए की ओर से विकसित की जा रही कॉलोनी में भरे पानी में मिले। थानाधिकारी परमेश्वरी ने बताया कि चिकनी मिट्टी होने के कारण प्रारंभिक तौर पर आशंका है कि पैर फिसलने से दोनों बच्चे पानी में गिर गए और डूब गए। पानी ऊपरी तौर पर साफ नजर आ रहा था, मगर कुछ ही दूरी पर बड़ा गड्ढा तकर्रीबन 8-10 फीट होगा, जिसमें गिर गए और दलदल में फंस गए। रात को उनकी तलाश की गई थी। आज सुबह शव पानी में ऊपर आ गए।

सर्पदंश से एक युवक की मौत : करौली-हिंडौन सड़क मार्ग पर स्थित जुंगीनपुरा गांव निवासी कुमार गौरव (31) पुत्र हर्दयाल गुर्जर कृषि कार्य कर रहा था। अकस्मात ही सर्प ने डस लिया। उपचार के लिए करौली सामान्य चिकित्सालय लाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

कार्यालय नगर निगम जोधपुर

पोलिटेक्निक कॉलेज परिसर के अन्दर, गौरव पथ, जोधपुर

फोन संख्या :-0291-2651491 ईमेलआईन :- 0291-2651473 E-mail: ceo_njn@rediffmail.com

क्रमांक:-सं./एफ-15/कार्य/ 2026 /RL-16906 दिनांक:- 11.08.2026

ई- निविदा सूचना क्रमांक RL-16900 दिनांक 11.08.2026

UBN No. DLB2627WSOB18178

जोधपुर नगर निगम द्वारा इच्छुक कार्य के अनुषंग/योग्यताधारी, डिजिटल विभुत लाईसेन्सधारी संवेदको, नगर निगम में पंजीकृत नियमानुसार **E-EWSD** श्रेणी संवेदको, अन्य विभाग में पंजीकृत **E-EWSD4** ऑन-लाईन "ई" टेण्डर प्रक्रिया से निगम शर्तों के अधीन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा के कार्य, योग्यता, शर्तों की समस्त जानकारी इंटरनेट पर eproc.raajasthan.gov.in अथवा sppp.raajasthan.gov.in अथवा <https://isp.raajasthan.gov.in/njnjdhpur> पर देखी जा सकती है।

अधीक्षण अभियंता
नगर निगम जोधपुर

राज.संवाद/सी/26/10098

कार्यालय नगरपरिषद सलूखर जिला-सलूखर (राज0)

क्रमांक:-न.प.स./ निर्माण / 2026-27 / 2159-2163 दिनांक :- 11.08.2026

अल्पकालीन निविदा सूचना 08 वर्ष 2026-27

नगरपरिषद सलूखर द्वारा उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदको से निर्धारित प्रपत्र में **E-Procurement** प्रक्रिया से www.eproc.raajasthan.gov.in पर ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। संवेदक द्वारा निविदा प्रपत्र, निविदा शर्तों व अन्य विस्तृत जानकारी इंटरनेट वेबसाइट www.sppp.raajasthan.gov.in और www.eproc.raajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

कुल निविदा के कार्य : 02 कार्य

निविदा की कुल लागत : रु 70,00 लाख

कुल धरोहर राशि : अनुमानित लागत की दू प्रतिशत

ऑनलाईन निविदा फार्म प्राप्त करने व जमा : 12 / 08 / 2026 प्रातः 12:00 बजे से 20 / 08 / 2026 सांय : 06:00 बजे तक

निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रोसेसिंग शुल्क : 12 / 08 / 2026 प्रातः 12:00 बजे से ऑनलाईन जमा कराने की अवधि 20 / 08 / 2026 सांय : 06:00 बजे तक

ऑनलाईन निविदा खोलने की दिनांक : 21 / 08 / 2026 दोपहर 12:00 बजे

NIB Code :- DLB2627A7093 UBN Code :-DLB2627WSOB18218 UBN Code :-DLB2627WSOB18219

राज.संवाद/सी/26/10090 आयुक्त, नगर परिषद सलूखर

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), जालोर

क्रमांक/ चुनाव / लेखा/2026/497 दिनांक: 14.08.2026

शुद्धि पत्र

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), जालोर द्वारा आगामी पंचायतीराज एवं नगरीय निजाम चुनाव 2026 एवं अन्य चुनावों के लिए विभिन्न ई-निविदा एवं खुली निविदा आमंत्रित की गई थी अपरिहार्य कारणों से निम्नानुसार निविदा में आंशिक संशोधन किया जाता है।

क्र. सं.	निविदा का विवरण	UBN No.	बिड प्रस्तुत करने की पूर्व अंतिम दिनांक	बिड प्रस्तुत करने की संशोधित अंतिम तिथि
1.	STATIONARY AND POLL MATERIAL	CJL2627 GLRC00016	18.08.2026; 01.00 PM	21.08.2026; 01.00 PM
2.	BALLOT PAPER AND OTHER PRINTING WORK	CJL2627 SLRC00017	14.08.2026; 01.00 PM	21.08.2026; 01.00 PM
3.	ALPHAHAR AND MEAL			

सार-समाचार

जालोर में डॉ. प्रदीप के. गावंडे ने सम्पर्क पोर्टल के कार्यों की समीक्षा की

जालोर, (कासं)। जिला कलैक्टर डॉ. प्रदीप के. गावंडे की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई, जिसमें संपर्क पोर्टल की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जिला कलैक्टर डॉ. प्रदीप के. गावंडे ने संपर्क पोर्टल पर प्राप्त परिवेदनाओं की विभागवार समीक्षा की तथा विभागीय अधिकारियों को संपर्क पोर्टल पर प्राप्त आमजन की परिवेदनाओं का त्वरित रूप से निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी औसत समय में कमी लाते हुए परिवेदनाओं का गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने जिले में राज्य सरकार के निर्देशानुसार ग्राम एवं ब्लॉक स्तर पर आयोजित होने वाली जनसुनवाई एवं समाधान व्यवस्था शिविर की समीक्षा करते हुए कहा कि विभागीय अधिकारी जनसुनवाई के दौरान जिले के नगरिकों की परिवेदनाओं का गुणवत्तापूर्ण समाधान करें। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर राजेंद्र सिंह चौदावार, डीएफओ जयदेव सिंह चारण, वन विभाग के एसीएफ भंवर सिंह सोढा, लेखाधिकारी भूपेंद्र मकवाना सहित अधिकारी-कार्मिक उपस्थित रहे।

रामसरोवर से नावें व अतिक्रमण हटाने की मांग

पोकरण, (कासं)। रामदेवरा पवित्र तीर्थस्थल रामदेवरा स्थित रामसरोवर तालाब से दो दर्जन से अधिक नावों एवं घाटों पर अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर बाबा रामदेव समाधि समिति के सदस्य आनंदसिंह तंवर सोमवार को भोजनशाला के सामने रामसरोवर घाट पर एक दिवसीय सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठे। उन्होंने प्रशासन से तालाब की पवित्रता बनाए रखने के साथ श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए घाटों से सभी प्रकार के अतिक्रमण तत्काल हटाने की मांग की। आनंदसिंह तंवर ने बताया कि रामदेवरा में बाबा रामदेवजी की समाधि के दर्शन के लिए प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में तालाब और सड़के घाटों की स्वच्छता, पवित्रता एवं व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। तंवर ने बताया कि इस मामले को लेकर 1० अगस्त को मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर प्रशासन से प्रभावी कार्रवाई की मांग की गई थी। ज्ञापन में कार्रवाई नहीं होने पर जन आंदोलन शुरू करने की चेतावनी भी दी गई थी। इसके बावजूद अभी तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं होने के कारण उन्हें सांकेतिक भूख हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा। तंवर ने चेतावनी दी कि यदि 17 अगस्त को उनकी मांगों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की जाती है तो 18 अगस्त से सर्व सहमति से आंदोलन को अलग रूप में आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने प्रशासन से रामसरोवर तालाब से सभी नावें, घाटों पर लगे स्टैंड तथा अन्य अतिक्रमण तत्काल हटाने और श्रद्धालुओं के लिए घाटों को सुचारु एवं सुरक्षित बनाने की मांग की।

मारोल में नेत्र जांच शिविर संपन्न

रेक्टर, (निंसें)। स्थानीय ग्राम पंचायत मारोल में दिनेशकुमार मुंकेशकुमार चौधरी द्वारा तथा ग्लोबल नेत्र हॉस्पिटल, आबूरोड तलहटी के सहयोग से एक निशुल्क नेत्र जांच शिविर का सफल आयोजन किया गया। शिविर में नेत्र विशेशज्ञ डॉ. अंजली द्वारा मरीजों की जांच की गई। इस दौरान कुल 75 मरीजों ने शिविर का लाभ उठाया तथा उन्हें निशुल्क दवावियों का विवरण भी किया गया। जांच के दौरान मोतिवालबंद के 16 मरीज चिन्हित किए गए, जिनमें से 11 मरीजों को सफल ऑपरेशन हेतु ग्लोबल हॉस्पिटल आबूरोड भेजा गया। इस शिविर में केंप भामशाह पूर्व सरचंग गणेशराम मेघवाल उमाराम सुथार, दिनेशकुमार मेघवाल वचन सिंह देवडा गोविन्दसिंह देवडा ओमप्रवी गोस्वामी छोगाराम पुरोहित चंदूलाल मेघवाल निंबाराम विक्रम मेघवाल, अशोक कुमार मेघवाल ,भंवरलाल सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

जेल में बंदी से एंड्राइड फोन बरामद

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर केंद्रीय कारागार में एक बार फिर विचाराधीन बंदी के पास एंड्राइड फोन बरामद हुआ है। अब इस बारे में जेल की तरफ से रातानाडा थाने में मामला दर्ज कराया गया है। रातानाडा पुलिस ने बताया कि जेल में तलाशी बनवारीलाल की तरफ से रिपोर्ट दी गई। इसमें बताया कि जेल में सिपाही अभियान के समय वाई 11 के पीछे बाथरूम के पास में एक विचाराधीन बंदी सुनील के पास से एंड्राइड फोन बरामद हुआ। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर अब जांच की जा रही है। जेल में मोबाइल कब और किसके द्वारा लाया गया, इसकी जांच की जा रही है।

गर्ग ने शोक संतप्तों को दी सात्वना

जालोर, (कासं)। राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने सोमवार को बापू नगर कॉलोनी, जालोर नगर निवासी उधमी मोहनलाल सोलंकी की माताजी सोनी देवी के निधन पर उनके आवास पर पहुंच कर दिवंगत आत्मा को श्रद्धासुमन अर्पित किए एवं शोकाकुल परिजनों को इस दु:खद घड़ी में ढांडस बंधाया। इस दौरान निजिन सोलंकी, राजेंद्र माहेश्वरी, गणेशराम चौधरी, नाथु सोलंकी व चौथाराम सुंदेशा उपस्थित रहे।

शातिर नकबजन गिरफ्तार

जोधपुर, (कासं)। विवेक विहार थाना क्षेत्र नंदवान गांव में 8 अगस्त की रात को हुई नकबजनी का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक शातिर नकबजन को पकड़ा है। आरोपी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर 2० लाख के जेवरत और 4 लाख की नगदी पर हाथ साफ किया था।

सायला में गर्ग ने विकास कार्यों का भूमि पूजन, शिलान्यास व लोकार्पण किया

जालोर, (कासं)। राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग के मुख्य आतिथ्य में रविवार को जिले के सायला ब्लॉक में कुल 1०.25 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन, शिलान्यास व लोकार्पण समारोह सम्पन्न हुआ। समारोह में अतिथियों का स्वागत किया गया।

कार्यक्रम के दौरान नगर पालिका सायला क्षेत्र में कुल 3.77 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। इनमें 2.27 करोड़ रुपये की लागत से सड़क एवं नाली निर्माण कार्य, 8० लाख रुपये की लागत से घर–घर कचरा संग्रहण वाहन, 2० लाख रुपये की लागत से अम्बेडकर ई–लाइब्रेरी का पुनरुद्धार कार्य तथा 5० लाख रुपये की लागत से 2०0 स्ट्रीट लाइट लगाने एवं डिवाइडर निर्माण कार्य शामिल है। इसी प्रकार नगर पालिका सायला क्षेत्र में 6.48 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। इनमें 3.25 करोड़ रुपये की लागत से नगर पालिका स्टेडियम का संपूर्ण रिनोवेशन एवं पुनर्निर्माण, 65 लाख रुपये की लागत से बस स्टैंड का पुनरुद्धार कार्य, 5० लाख रुपये की लागत से वीरणा तिराहों पर उड़ान विमान, 2० लाख रुपये की लागत से श्मशान विकास कार्य, 5० लाख रुपये की लागत से विभिन्न स्थानों पर हाई मास्क एवं सेमी हाई मास्क लगाने का कार्य, 8० लाख रुपये की लागत से सीवरेंज कार्य, लाइट एवं सड़क मरम्मत संबंधी कार्य तथा 25 लाख रुपये की लागत से 5०० स्ट्रीट लाइट लगाने के कार्यों का शिलान्यास

जोधपुर नगर निगम के 1००० वार्डों में से 34 महिलाएं पार्षद होंगी

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर नगर निगम के 1०० वार्डों के लिए आज लॉटरी निकाली गई। 1०० वार्डों में से ओबीसी महिला के लिए 7, एससी महिला के लिए 4, एसटी महिला के लिए 1 और अनारक्षित ओपन महिला के लिए 22 वार्ड रिजर्व किए गए हैं।

इस बार शहर में सभी कैटेगरी को मिलाकर कुल 34 महिलाएं पार्षद होंगी। ओबीसी ओपन के 13 वार्ड, एससी के 9 और एसटी ओपन का एक वार्ड आरक्षित किया गया है। इसके अलावा 43 वार्ड अनारक्षित ओपन कैटेगरी में रखे गए हैं। यानी इन 43 वार्डों में किसी भी वर्ग का पुरुष उम्मीदवार चुनाव लड़ सकेगा।

मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर

जालोर जिले के वार्डों का लॉटरी से आरक्षण तय

जालोर, (कासं)। नगर निकायों के आम चुनाव-2०26 के तहत नगर परिषद जालोर, नगर पालिका आहोर, नगर पालिका सायला, नगर पालिका भीनमाल एवं नगर पालिका सांचौर के वार्डों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए आरक्षण निर्धारित करने के लिए लॉटरी प्रक्रिया सोमवार को जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलैक्टर) डॉ. प्रदीप के. गावंडे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई।

जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलैक्टर) डॉ. प्रदीप के. गावंडे ने बताया कि लॉटरी प्रक्रिया के तहत नगर परिषद जालोर के 4० वार्डों, नगर पालिका आहोर के 25 वार्डों, नगर पालिका सायला के 25 वार्डों, नगर पालिका भीममाल के 4० वार्डों तथा नगर पालिका सांचौर के 35 वार्डों में आरक्षित एवं अनारक्षित वार्ड निर्धारित किए गए।

नगर परिषद जालोर के 4० वार्डों में अनारक्षित वार्ड 3, 4, 6, 7, 1०, 12, 14, 15, 2०, 21, 30, 33, 34, 37 एवं 4०, अनारक्षित महिला वार्ड 1, 5, 9, 11, 32, 35 एवं 38, ओबीसी आरक्षण वार्ड 13, 16, 19, 25 एवं 39, ओबीसी महिला आरक्षण वार्ड 22, 26, 36 में निर्धारित हुआ। वहीं एससी आरक्षण के तहत वार्ड 8, 17, 18, 23 एवं 31 तथा एससी महिला आरक्षण के तहत वार्ड 2 एवं 24 निर्धारित किए गए। इसी प्रकार, एसटी आरक्षण के तहत वार्ड 27 एवं 29 तथा एसटी महिला आरक्षण के तहत वार्ड 28 निर्धारित हुए।

नगर पालिका आहोर के 25 वार्डों में अनारक्षित वार्ड 6, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 2०, 24 एवं 25, अनारक्षित महिला वार्ड 8, 9, 17, 19 एवं 21, ओबीसी आरक्षण वार्ड 14, 22 एवं 23, ओबीसी महिला आरक्षण

■ **नगर परिषद जालोर, आहोर, सायला, भीनमाल एवं सांचौर के वार्डों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए आरक्षण निर्धारित**

वार्ड 7 एवं 1० में निर्धारित हुआ। वहीं एससी आरक्षण के तहत वार्ड 2, 3 एवं 4 एससी महिला आरक्षण के तहत वार्ड 5 निर्धारित किए गए। एसटी आरक्षण के तहत वार्ड 1 निर्धारित किया गया। नगर पालिका सायला के 25 वार्डों में अनारक्षित वार्ड 1, 2, 6, 1०, 11, 13, 15, 21 एवं 22, अनारक्षित महिला वार्ड 5, 17, 24 एवं 25, ओबीसी आरक्षण वार्ड 4, 18 एवं 19, ओबीसी महिला आरक्षण वार्ड 9 में निर्धारित हुआ। वहीं एससी आरक्षण के तहत वार्ड 7, 8, 14 एवं 2० एससी महिला आरक्षण के तहत वार्ड 3 व 23 निर्धारित किए गए। इसी प्रकार एसटी आरक्षण के तहत वार्ड 12 व एसटी महिला आरक्षण के तहत वार्ड 16 निर्धारित हुए।

नगर पालिका भीनमाल के 4० वार्डों में अनारक्षित वार्ड 3, 4, 5, 9, 1०, 11, 13, 18, 2०, 24, 25, 27, 32, 33 एवं 35, अनारक्षित महिला वार्ड 6, 16, 17, 19, 26, 29 एवं 38, ओबीसी आरक्षण वार्ड 7, 15, 22, 31 एवं 39, ओबीसी महिला आरक्षण वार्ड 8, 12 एवं 3० में निर्धारित हुआ।

वहीं एससी आरक्षण के तहत वार्ड 14, 21, 23, 36 एवं 4०, एससी महिला आरक्षण के तहत वार्ड 34 एवं 37 निर्धारित किए गए। इसी प्रकार, एसटी आरक्षण के तहत वार्ड 1 एवं 28 व एसटी महिला आरक्षण के तहत वार्ड

लॉटरी शुरू होने से पहले जब कलैक्टर वार्डों की जानकारी दे रहे थे तो कांठोस जिलाध्यक्ष ओमकार वर्मा ने ओबीसी वार्ड रिजर्वेशन को लेकर सवाल किए। इस पर कलैक्टर ने इस पूरे प्रोसेस को ब्रीफ किया। इसके साथ ही लॉटरी कैसे निकाली जाएगी ये भी सभी को बताया।

ओबीसी रिजर्वेशन और वार्डों को लेकर लॉटरी निकालने के प्रोसेस को कलैक्टर ने सभी के साथ शेयर किया। इस दौरान बंद डिब्बे में अलग-अलग कैटेगिरी के वार्डों की पर्चियां रखी गईं। इसके बाद स्कूली बच्चियों से एक-एक कर कैटेगरी वाइज लॉटरी सभी के सामने निकाली।

जैसे ही जोधपुर नगर निगम के

लॉटरी शुरू होने से पहले जब कलैक्टर वार्डों की जानकारी दे रहे थे तो कांठोस जिलाध्यक्ष ओमकार वर्मा ने ओबीसी वार्ड रिजर्वेशन को लेकर सवाल किए। इस पर कलैक्टर ने इस पूरे प्रोसेस को ब्रीफ किया। इसके साथ ही लॉटरी कैसे निकाली जाएगी ये भी सभी को बताया।

ओबीसी रिजर्वेशन और वार्डों को लेकर लॉटरी निकालने के प्रोसेस को कलैक्टर ने सभी के साथ शेयर किया। इस दौरान बंद डिब्बे में अलग-अलग कैटेगिरी के वार्डों की पर्चियां रखी गईं। इसके बाद स्कूली बच्चियों से एक-एक कर कैटेगरी वाइज लॉटरी सभी के सामने निकाली। जैसे ही जोधपुर नगर निगम के लॉटरी शुरू होने से पहले जब कलैक्टर वार्डों की जानकारी दे रहे थे तो कांठोस जिलाध्यक्ष ओमकार वर्मा ने ओबीसी वार्ड रिजर्वेशन को लेकर सवाल किए। इस पूरे प्रोसेस को ब्रीफ किया। इसके साथ ही लॉटरी कैसे निकाली जाएगी ये भी सभी को बताया।

लॉटरी प्रक्रिया के दौरान संबंधित अधिकारी-कार्मिक सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, मीडिया कर्मी व आमजन उपस्थित रहे। आरक्षण की प्रक्रिया निर्धारित नियमों एवं प्रावधानों के अनुसार पारदर्शी तरीके से कराई गई। **बालोतरा संवाददाता के अनुसार :** नगर निकाय चुनाव 2०26 की तैयारियों के तहत सोमवार को जिले के समस्त नगर निकायों के वार्डों के आरक्षण के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सुशील कुमार यादव की अध्यक्षता में लॉटरी निकाली गई।

जिला निर्वाचन अधिकारी सुशील कुमार यादव की अध्यक्षता में नगर परिषद बालोतरा के 55 वार्डों, नगर पालिका समदडी के 25 वार्डों, नगर पालिका सिवाणा के 25 वार्डों, नगर पालिका जसोल के 2० वार्डों, नगर पालिका सिमणगरी के 2० वार्डों, नगर पालिका धोरीमन्ना के 2० वार्डों, नगर पालिका गुडामालानी के 2० वार्डों के आरक्षण के लिए लॉटरी निकाली गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार इस दौरान जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में पारदर्शी एवं शान्तिपूर्ण प्रक्रिया के साथ नगर विकास न्यास के सर्चिव अशोक कुमार एवं चुनाव शाखा कार्मिकों के सहयोग से नन्ही बालिकाओं के द्वारा वार्ड आरक्षण की लॉटरी निकाली गई।

1०० वार्डों की लॉटरी प्रक्रिया पूरी हुई। यहां मौजूद दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं और पुरे पार्षदों ने नारे लगाए। लॉटरी के दौरान हर बार पर्चियों से भरे डिब्बे को बंद कर उसे हिलाया गया। इसके बाद लॉटरी निकाली गई।

इन 1०० वार्डों में से 56 वार्ड ऐसे हैं, जहां 1० हजार या फिर इससे ज्यादा जनसंख्या है। बाकी वार्डों में 1० हजार से कम जनसंख्या है। इन 1०० वार्डों में वार्ड नंबर 87 वोटर्स केलिहाज से सबसे बड़ा है, जहां 13 हजार से ज्यादा जनसंख्या है।

वहीं, वार्ड नंबर 1० में सबसे कम करीब 4 हजार जनसंख्या है। इसमें राजस्व गैर पाल (पूर्व) का हिस्सा शामिल है।

घायल चिंकारे ने तड़पने के बाद दम तोड़ा

■ **ग्रामीणों का आरोप है कि समय पर रेस्क्यू और उपचार नहीं मिला**

धोरीमन्ना, (नि.संं)। धोरीमन्ना वनरंज क्षेत्र के लोलो की बेरी ग्राम में एक घायल चिंकारे ने करीब चार घंटे तक तड़पने के बाद दम तोड़ दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि समय पर रेस्क्यू और उपचार मिल जाता तो चिंकारे को जान बचाई जा सकती थी।

खिचडों की ढाणी के पास दो चिंकारे अटखेलियां कर रहे थे। इसी दौरान वहां पढ़े तार में एक चिंकारे के सोंग फंस गए।दोनों चिंकारों के बीच छटपटाहट में सोंग उलझने से वे आपस में गुंथमगुंथ्ता हो गए और गंभीर रूप से घायल हो गए।चिकारों की चीख-पुकार सुनकर वन्यजीव प्रेमी भार्गवरथराम खिचड मौके पर पहुंचे। उन्होंने तार काटकर दोनों चिंकारों को मुक्त किया।एक घायल चिंकारा वहां से भाग गया, जबकि दूसरा गंभीर हालत में मौके पर ही पड़ा रहा। ग्रामीणों ने धोरीमन्ना वन विभाग को सूचना दी। ग्रामीणों के अनुसार रेस्क्यू वाहन उपलब्ध नहीं होने की बात कही गई। उन्होंने जम्भेश्वर वाइल्डलाइफ एनवायरमेंट संस्था के जिलाध्यक्ष भंवरलाल भादू को सूचना दी। भादू तत्काल मौके पर पहुंचे और घायल चिंकारे को रेस्क्यू कर उपचार दिलाने के लिए वन विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया। भंवरलाल भादू के अनुसार उन्होंने रंजर से मौके पर रेस्क्यू स्टाफ भेजने का आग्रह किया, लेकिन उन्हें बताया गया कि कर्मचारों मंत्री के गुडामालानी कार्यक्रम में व्यस्त हैं। इसके बाद भी घायल चिंकारे को बचाने के लिए कई बार प्रयास किए गए, लेकिन समय पर उपचार और रेस्क्यू नहीं हो सका। ग्रामीणों के मुताबिक चिंकारा दोपहर करीब 2 बजे से शाम 6 बजे तक घायल अवस्था में तड़पता रहा।

दो बच्चियों ने नगरपरिषद जैसलमेर एवं पालिका पोकरण के वार्डों की लॉटरी निकाली

दो बच्चियों ने नगरपरिषद जैसलमेर एवं पालिका पोकरण के वार्डों की लॉटरी निकाली

जैसलमेर, (नि.संं)। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पालना में सोमवार को जिला निर्वाचन अधिकारी (कलैक्टर) अनुपमा जोरवाल की अध्यक्षता में जिला कलक्टरी सभागार में नगरपरिषद जैसलमेर एवं नगरपालिका पोकरण के वार्डों की लॉटरी निकाली गई। नन्ही-मुन्ही दो बालिकाओं द्वारा राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के समक्ष पूर्ण पारदर्शिता के साथ वार्डों के आरक्षण की लॉटरी निकाली गई।

प्राप्त जनकारी के अनुसार निकाली गई लॉटरी के माध्यम से दोनों निकायों में सामान्य, सामान्य महिला, अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति महिला, अनुसूचित जन जाति एवं अनुसूचित जन जाति महिला के वार्डों का निर्धारण हुआ।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी (एडीएम) परसराम सैनी ने बताया कि नगरपरिषद जैसलमेर के कुल 45 वार्डों में से जनसंख्या के अनुपात में 5 वार्ड अनुसूचित जाति, 2 वार्ड अनुसूचित जन जाति , 9 वार्ड अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 29 वार्ड सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित हुए। लॉटरी गई लॉटरी के अनुसार अनुसूचित जाति (ओपन) के लिए वार्ड संख्या 11, 31 व 38 तथा वार्ड संख्या 12 व 39 अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित हुए। इसी प्रकार अनुसूचित जन जाति (ओपन) के लिए वार्ड संख्या 9 तथा अनुसूचित जन जाति महिला के लिये वार्ड संख्या 1० आरक्षित हुआ।

इसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग (ओपन) के लिये वार्ड संख्या 14, 15, 17, 18, 2० व 34 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए वार्ड संख्या 16, 23 एवं 43 आरक्षित हुए। सामान्य वर्ग (ओपन) के लिए वार्ड संख्या

बाड़मेर में बच्चों ने पर्ची के माध्यम से वार्ड आरक्षण लॉटरी निकाली

बाड़मेर, (नि.संं)। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर सोमवार को जिला कलक्टर-चिन्मयी गोपाल की अध्यक्षता में बाड़मेर नगर परिषद एवं चौहटन नगर पालिका के वार्डों की आरक्षण निर्धारित के लिए लॉटरी प्रक्रिया संपादित की गई।

कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में बाड़मेर नगर परिषद के 55 एवं चौहटन नगर पालिका के 2० वार्डों में पारदर्शिता के साथ लॉटरी के जरिए आरक्षण का निर्धारित हुआ। बाड़मेर नगर परिषद एवं इसके उपरांत चौहटन नगर पालिका के वार्डों में सीटों का निर्धारण करने के लिए विधिवत प्रक्रिया के तहत बच्चों के माध्यम से लॉटरी निकाली गई।

कार्यालय ग्राम पंचायत विबलसर पंचायत समिति, जालोर	
क्रमांक-ग्रा/मन/ग्रा/2०26-27/135	दिनांक : 14/०8/2०26
ई-निविदा सूचना संख्या ०2/2०26-27	
पंचायत समिति जालोर के अधीनस्थ ग्राम पंचायत विबलसर के लिए वित्तीय वर्ष 2०26-27 की अवधि के दौरान महत्वा गांधी नरेंग योजना/बीडी जी रामजी योजना एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अन्य योजनाओं में करये जाने वाले कार्यों के लिए निर्माण सामग्री एवं उपकरण की आपूर्ति हेतु राजस्थान लोक उपायन पारदर्शिता अधिनियम 2०12 एवं राजस्थान लोक उपायन पारदर्शिता नियम 2०13 (अधिनियम संशोधित) के अनुसार राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के तहत वस्तु एवं सेवाकर (GST) अधिनियम 2०17 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा पंजीकृत अनुभवी एवं इच्छुक विनिर्माता (ओ) / विक्रेता (ओ) / फर्मो / संबद्धों) / आपूर्तिकर्ताओं से, जो किसी भी राजकीय संस्था / उपक्रमों से बोनो लगाने से विवर्जित/ ब्लैक लिस्टेड नहीं हो, से निष्धारित प्रत्र में ई-प्रोक्युरमेंट प्रक्रिया से निविदाएं आमंत्रित की जाती है। ई-निविदा सबीक्ष समस्त विस्तृत विवरण कार्यालय नोटिस बोर्ड तथा www.eproc.rajasthan.gov.in एवं www.sppr.rajasthan.gov.in पर अवलोकन की जाकर डाउनलोड कर www.eproc.rajasthan.gov.in पर ई-निविदा ऑनलाईन अपलोड की जा सकती है।	
NIB No.ZJR2627A0596	
प्रयाक	UBN No. ZJR2627GLOB00772
ग्राम पंचायत विबलसर पंचायत समिति जालोर	ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत विबलसर पंचायत समिति जालोर

कार्यालय ग्राम पंचायत साँधू पंचायत समिति, जालोर	
क्रमांक-ग्रा/मन/ग्रा/2०26-27/142	दिनांक : 14/०8/2०26
ई-निविदा सूचना संख्या ०2/2०26-27	
पंचायत समिति जालोर के अधीनस्थ ग्राम पंचायत साँधू के लिए वित्तीय वर्ष 2०26-27 की अवधि के दौरान महत्वा गांधी नरेंग योजना/बीडी जी रामजी योजना एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अन्य योजनाओं में करये जाने वाले कार्यों के लिए निर्माण सामग्री एवं उपकरण की आपूर्ति हेतु राजस्थान लोक उपायन पारदर्शिता अधिनियम 2०12 एवं राजस्थान लोक उपायन पारदर्शिता नियम 2०13 (अधिनियम संशोधित) के अनुसार राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के तहत वस्तु एवं सेवाकर (GST) अधिनियम 2०17 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा पंजीकृत अनुभवी एवं इच्छुक विनिर्माता (ओ) / विक्रेता (ओ) / फर्मो / संबद्धों) / आपूर्तिकर्ताओं से, जो किसी भी राजकीय संस्था / उपक्रमों से बोनो लगाने से विवर्जित/ ब्लैक लिस्टेड नहीं हो, से निष्धारित प्रत्र में ई-प्रोक्युरमेंट प्रक्रिया से निविदाएं आमंत्रित की जाती है। ई-निविदा सबीक्ष समस्त विस्तृत विवरण कार्यालय नोटिस बोर्ड तथा www.eproc.rajasthan.gov.in एवं www.sppr.rajasthan.gov.in पर अवलोकन की जाकर डाउनलोड कर www.eproc.rajasthan.gov.in पर ई-निविदा ऑनलाईन अपलोड की जा सकती है।	
NIB No.ZJR2627A0596	
प्रयाक	UBN No. ZJR2627GLOB00772
ग्राम पंचायत साँधू पंचायत समिति जालोर	ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत साँधू पंचायत समिति जालोर

कार्यालय नगर परिषद बाड़मेर (राजस्थान)

E-mail : mbbarmerraj@gmail.com PH. NO. 02982-220098

क्रमांक : एफ-08/भूमि/ 2026-27 / 5888 दिनांक : 10.08.2026

आपत्ति आमंत्रण सूचना

एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद बाड़मेर में निम्न आवेदनकर्ताओं द्वारा 689/ /स्टेटघान/ /कच्ची बस्ती/ की होडक के तहत नियमन प्राप्त गया है :-

क्र. सं.	आवेदक का नाम वन विभा/पति का नाम	कॉलोनी का नाम	वर्ग/मीटर
1.	श्रीमति सुशीला देवी पत्नी श्री लेखाराम	सरदारपुरा	154.58
२.	श्री तरण कुमार पुत्र श्री अकाशचन्द रामदास	रामगढा की गली	84.44
3.	श्रीमती जानकी देवी पत्नी श्री पुरुषोत्तमदास	माढवी नगर	3१०.6०
4.	श्री रमेश कुमार पुत्र श्री प्रमुरम	सरदारपुरा	1०9.85
5.	श्री सरोिता पत्नी श्री जितेन्द्र कुमार अग्रवाल	खोखेर नगर	139.35
6.	श्री मणुश्री पत्नी श्री जितेन्द्र कुमार अग्रवाल	खोखेर नगर	139.35
7.	श्रीमति पुष्पा जैन पत्नी श्री बाबूलाल	पुराना जालावर	2०8.1०
8.	श्री हिंगलजयन पुत्र श्री हनुमान	सुनवरी का वार	11०.64
9.	श्री पुरवाराम पुत्र श्री रामेश्वर	कल्याणपुरा नामा नंद	111.48
1०.	श्री भूमिश्री पुत्र श्री उमदेवसिंह	लिल्दिखा बाघा	2०2.29
11.	श्री भणोरिश पुत्र श्री प्रतापसिंह	लिल्दिखा बाघा	118.54
12.	श्री मणुश्री पुत्र श्री प्रतापसिंह	लिल्दिखा बाघा	118.54
1३.	श्री किशोर पुत्र श्री सत्यनन्द	आनवली का वार	151.66
14.	श्री नारायण पुत्र श्री राखवल	गायत्री चौक, न्यूटोरी का वार	84.०७
15.	श्री सुब्रह्म जयन पुत्र श्री नरसिंहयन	सरदारपुरा	125.73
1६.	श्री जितेन्द्र मोदी पुत्र श्री पुरुषोत्तमदास मोदी	गंभीरी चौक	232.26
17.	श्री बबेश्वर पुत्र रामेश्वरदास	मेठ सुनवरी का वार, सुनाष चौक	111.48
1८.	श्री दिपक कुमार पुत्र श्री लालचन्द	कल्याणपुरा नामा नं	०3
19.	श्री प्रदीप पुत्र श्री दिनेश सोनी	पुराना जालावर, सुनाष चौक	०9.29

उक्त नियमन/पट्टा पत्रावली के सम्बन्ध में किसी आम व्यक्ति, स्थान या अधिकारी, किसी संस्था या को कोई भी आपत्ति हो या माननीय न्यायालय में कोई वाद हो/स्थान आदेश पास्ति हो/देवदत्त के नील-मीर किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय सभ्य में उपस्थित होकर आपत्ति पत्र/वाद म्याद गुजरेने आपत्ति म्याद नहीं होगी एवं अग्रिम कार्यवाही कर दी जायेगी।

रहित रहें। राज.संवा. वकी/ 26/ 10136

अ

उक्त नियमन /पट्टा पत्रावली को सम्बन्ध में किसी आम व्यक्ति, छात्र याक्ति, किसी संस्था इत्यादि को कोई भी आपत्ति हो या मानवीय न्यायालय में कोई वाद हो/ स्थान आदेश पारित हो तो 07 दिवस के भीतर–भीतर किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें। बाद न्याय गुजजने आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं अंतिम कार्यवाही कर दी जावेगी। सूचित रहे।
राज.संवाद /सी/ 26 / 1०136

आयुक्त

मुख्यमंत्री भजनलाल के महत्वपूर्ण जल समझौतों से विकास की गंगा बहेगी- शिवराज सिंह चौहान

केन्द्रीय कृषि मंत्री तथा मुख्यमंत्री ने बारां व झालावाड़ में 1258 करोड़ के 98 विकास कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास किया

बारां/जयपुर, 17 अगस्त। केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में हुए पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना समझौते से 4 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा। इसी प्रकार, यमुना जल से जुड़ा महत्वपूर्ण समझौता भी हुआ है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में निरंतर विकास की गंगा बहेगी। केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री सोमवार को बारां की कृषि उपज मंडी में बारां-झालावाड़ के विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे।

केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि बारां, झालावाड़, कोटा के कृषि क्षेत्र में विकास का रोडमैप बनाया जाएगा। इससे किसान नई फसलों की पैदावार कर सकेंगे और उनकी आमदनी बढ़ेगी।

कार्यक्रम के दौरान केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत राजस्थान के लिए 3 हजार 473 करोड़ रुपये की लागत से 2 लाख 89 हजार 355 नवीन आवास निर्माण तथा कृषि विभाग की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं कृषि उन्नत योजना के लिए 340 करोड़ 59 लाख रुपये की स्वीकृति के पत्र सौंपे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पीएम-किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, पीएम-कुसुम और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं ने किसानों की आय को सुरक्षित करने,



केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को बारां की कृषि उपज मंडी में बारां-झालावाड़ के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।

कृषि लागत कम करने और ऊर्इ आसान ऋण उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बारां एवं झालावाड़ जिलों में 1 हजार 258 करोड़ के 98 विकास कार्यों का

शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। पिछले ढाई साल में बारां के समग्र विकास के लिए 3 हजार 316 करोड़

■ **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पीएम-किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, पीएम-कुसुम तथा किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं ने किसानों की आय को सुरक्षित करने व कृषि लागत कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।**

एवं झालावाड़ के लिए 6 हजार 474 करोड़ सहित कुल 10 हजार करोड़ से अधिक का बजट आवंटित किया गया है।

इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभा स्थल पर बारां जिला प्रशासन की विकास कार्यों एवं विभागीय योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनों का अवलोकन किया। इस अवसर पर ग्रामीण विकास राज्यमंत्री ओटाराम देवासी, सांसद दुष्यंत सिंह, विधायक प्रताप सिंह सिंघवी, ललित मीणा, राधेश्याम बैरवा, स्थानीय जनप्रतिनिधिगण सहित, वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।

नितिन नबीन ... आईएसआई के शहज़ाद भट्टी नेटवर्क के 255 संदिग्ध गिरफ्तार

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मंगल को राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम में राजस्थान के नेताओं को मिली अहम जिम्मेदारियों के बाद प्रदेश की राजनीति में भी इसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। एक तरफ वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर बनाए रखा गया है, तो दूसरी ओर सतीश पूनिया को राष्ट्रीय महामंत्री बनाकर संगठन में उनका कद बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में भाजपा की सरकार है। ऐसे में प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की राष्ट्रीय संगठन में मौजूदगी आने वाले समय में केन्द्र और प्रदेश संगठन के बीच समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। नई नियुक्तियों से एक बात साफ है कि भाजपा ने राजस्थान के अनुभवी, संगठनात्मक और सामाजिक आधार वाले नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी देकर प्रदेश को संगठन की नई रणनीति में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। अब इन नियुक्तियों का असर राजस्थान भाजपा के भीतर आगामी राजनीतिक और संगठनात्मक समीकरणों पर कितना पड़ता है, इस पर सबकी नजर रहेगी।

नई दिल्ली, 17 अगस्ता।

सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क (एसबीएन) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 राज्यों में 253 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। इस नेटवर्क के खिलाफ 80 से अधिक प्राथमिकी दर्ज की गई है।

स्वतंत्रता दिवस के आसपास एसबीएन से जुड़ी संभावित गड़बड़ियों को रोकने के लिए 12 अगस्त को राज्य पुलिस बलों के साथ रियल-टाइम खुफिया जानकारी साझा करने वाली प्रणाली

- **सुरक्षा एजेंसियों ने स्वतंत्रता दिवस से पहले कार्यवाही कर आतंकवादियों के मंसूबे नाकाम किये**
- **केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक पोस्ट में यह जानकारी दी।**

के जरिए समन्वित बहु-राज्यीय अभियान चलाया गया। इसमें 14 राज्यों में 253 लोगों को हिरासत में लिया गया है।

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मोदी सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई

कतर में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्राप्तकर्ता की यूपीआई आईडी के साथ जरूरी पहचान संबंधी जानकारी देनी होगी। भारत में ऐसे प्रचार करने वाले व्यक्ति को अपने यूपीआई ऐप में विदेश से वन प्राप्त करने की सुविधा सक्रिय करनी होगी। इसके बाद भेजी गई राशि सीधे उसके यूपीआई से जुड़े बैंक खाते में जमा हो जाएगी। एक लेनदेन में न्यूनतम 10 कतर रियाल और अधिकतम 4,000 कतर रियाल भेजे जा सकेंगे। हालांकि, एक लेनदेन की अधिकतम भारतीय मुद्रा में सीमा एक लाख रुपये के बराबर होगी। प्रत्येक लेनदेन पर 15 कतर रियाल का सेवा शुल्क लिया जाएगा।

विधानसभा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के अनुरूप संचालित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि सभी दल विधानसभा की गरिमा बनाए रखते हुए सत्र के सफल संचालन में सहयोग करेंगे।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मामले में, सरकार ने आरोप लगाया था कि उत्पाद का प्रचार वास्तव में विमल तंबाकू उत्पादों के लिए संश्लेषित विज्ञापन है। इस कानूनी विवाद ने एक बुनियादी समस्या को उजागर किया: केवल तंबाकू और गैर-तंबाकू उत्पादों के लिए एक ही ब्रांड नाम का होना अपने आप यह साबित नहीं करता कि विज्ञापन गैर-कानूनी है। रेगुलेटर को दोनों के बीच यह संबंध साबित करना होगा और दिखाना होगा कि देखने में वैध उत्पाद का विज्ञापन असल में प्रतिबंधित उत्पाद का प्रचार कर रहा है।

सबूत जुटाने की इस चुनौती की वजह से यह प्रथा अब भी ऐसे घुंघुंले क्षेत्र (ग्रे एरिया) में बनी हुई है, जहाँ कानून की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है।

तथापि, विज्ञापन की रणनीति अब और भी बेहतर होती जा रही है। कोई तंबाकू ब्रांड किसी कानूनी ब्रांड विस्तार (ब्रांड एक्सटेंशन) के जरिए लोगों के बीच अपनी पहचान बनाए रख सकता

है, जबकि विज्ञापन में उसी नाम, लोगो, रंग, सेलिब्रिटी, स्लोगन और विजुअल पहचान का इस्तेमाल किया जाता है, जो प्रतिबंधित उत्पाद से जुड़े होते हैं। ग्राहकों को ब्रांड पहचानने के लिए तंबाकू उत्पाद देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती।

इसीलिए रेगुलेटरी टेस्ट को मुख्य रूप से इरादा साबित करने पर आधारित होने के बजाय टोस और स्पष्ट पैमानों पर आधारित होना चाहिए।

रेगुलेटर यह जांच सकते हैं कि क्या इसी ब्रांड का इस्तेमाल तंबाकू उत्पादों के लिए भी किया जाता है, क्या कथित रूप से वैध उत्पाद का अपना पर्याप्त और स्वतंत्र रूप से चलने वाला कारोबार है; क्या उसका वितरण और बिक्री वास्तव में होती है; क्या विज्ञापन संबंधी प्रतिबंध लागू होने से पहले वह वास्तव में एक असली उत्पाद के तौर पर मौजूद था; और क्या उसका विज्ञापन तंबाकू ब्रांड की खास पहचान को बहुत करीब से दोहराता है।

जहाँ इनमें से कई संकेत एक साथ

शहजाद ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पूनावाला ने भाजपा और उसके शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा और बीएल संतोष से उन्हें लगातार मार्गदर्शन और सहयोग मिला।

उन्होंने कहा कि भाजपा और व्यापक संघ परिवार ने उन्हें जो अवसर और मंच प्रदान किया, उसके लिए वे सदैव कृतज्ञ रहेंगे। उन्होंने कहा कि एक युवा, पसमांदा मुस्लिम और गैर-वंशवादी व्यक्ति को भाजपा ने अवसर प्रदान किया। पूनावाला ने कहा कि वे उस पार्टी और राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद को अलविदा कह रहे हैं, जिसे वे बेहद पसंद करते हैं।

“दिमागी नक्सल” ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पारंपरिक राजनीतिक दलों से स्वतंत्र होकर खुद को संघटित किया है।

स्पष्ट रूप से, मोदी का यह संदेश वामपंथी विचारधारा वाले बुद्धिजीवियों, शिखाविदों, कार्यकर्ताओं, नागरिक समाज की आवाजों और सरकार के आलोचकों को निशाना बनाता है, जिन्हें भाजपा लंबे समय से “अर्बन नक्सल” कहती रही है।

इसमें असहमति, विशेषकर शासन, शिक्षा व्यवस्था की निफलताओं या हिंदुत्व की प्राथमिकताओं की आलोचना, को वैध राजनीतिक विरोध के बजाय माओवादी विद्रोह के वैचारिक विस्तार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

कांग्रेस ने इस टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने इस टिप्पणी को हताशा का पक्का संकेत बताया।

दिखाई दें, वहाँ विज्ञापन देने वाले पर यह साबित करने की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ब्रांड विस्तार वास्तव में एक वास्तविक और स्वतंत्र कारोबार है। सेलिब्रिटी के विज्ञापन में शामिल होने की भी विशेष रूप से जाँच होनी चाहिए। कोई एक्टर यह तर्क दे सकता है कि उसने इलायची का विज्ञापन किया, तंबाकू का नहीं। लेकिन अगर विज्ञापन का मुख्य मकसद प्रतिबंधित तंबाकू ब्रांड की पहचान को लाखों उपभोक्ताओं तक पहुँचाना है, तो इस अंतर को सही ठहराना लगातार मुश्किल हो जाता है।

उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि वैध कारोबारों को कानूनी उत्पादों का विज्ञापन करने से रोका जाए। उद्देश्य यह होना चाहिए कि किसी कानूनी उत्पाद को गैर-कानूनी उत्पाद के विज्ञापन के लिए सुविधाजनक माध्यम बनने से रोका जाए।

इसलिए भारत को ब्रांड विस्तार के लिए एक अधिक स्पष्ट और तकनीक से स्वतंत्र नियम की जरूरत है, जिसमें

झारखंड के मुख्यमंत्री ने छात्रों की मांग मानी, परीक्षा रद्द की

- **मुख्यमंत्री सोरेन की घोषणा पर आंदोलनरत छात्रों ने खुशी जताई, पर सीबीआई जांच की मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की घोषणा की**

- **मुख्यमंत्री सोरेन ने लखनऊ की डेटा प्रोसेसिंग और परीक्षा करवाने वाली संस्था टीएसआर डेटा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं व भर्तियों को रद्द करने की घोषणा की।**

छात्र नेता देवेन्द्र नाथ महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फैसले के लिए बधाई दी और इसे छात्रों के आंदोलन की बड़ी सफलता बताया।

हालांकि, आंदोलन कर रहे कुछ छात्रों का कहना है कि सरकार की ओर से महत्वपूर्ण मांगें मान ली गई हैं, लेकिन उनका आंदोलन अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। छात्रों ने कहा कि परीक्षाएं और भर्तियाँ रद्द करने की घोषणा स्वागत योग्य है, लेकिन कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच भी जरूरी है।

छात्रों की प्रमुख मांग अब पूरे मामले की सीबीआई जांच को लेकर है। उनका कहना है कि जब तक सरकार सीबीआई जांच कराने पर स्पष्ट निर्णय नहीं लेती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों का कहना है कि केवल परीक्षाएं रद्द करने से पूरे मामले की सच्चाई सामने नहीं आएगी। दावाियों की पहचान और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए स्वतंत्र जांच जरूरी है।

दूसरी तरफ, परीक्षा में सफल अर्थार्थियों ने मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया। उनका कहना है, "हम लोगों का क्या दोष है, जो हमारी परीक्षा रद्द कर दी गई?"

जेपीएससी विवाद के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखे पत्र से भी मामला राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो गया था। राहुल गांधी ने छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से लेने और उनके समाधान की दिशा में पहल करने की बात कही थी।

भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई टीम घोषित की

राममाधव राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, स्मृति ईरानी राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त, पीयूष गोयल कोषाध्यक्ष बने

- **नई टीम में महिलाओं और पूर्वोत्तर क्षेत्र को विशेष तवज्जो दी गई है तथा संगठनात्मक अनुभव, युवा ऊर्जा व क्षेत्रीय संतुलन पर ध्यान दिया गया है।**

पुर्देशवरी, रेखा वर्मा, वर्षाबेन नरेंद्रभाई दोशी, भारती प्रवीण पवार, मनप्रती सिंह बादल, लाल सिंह अर्मा, एम. नागराज, तारिक मंसूर और मधुचंद्र कर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। बीएल संतोष राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) होंगे। शिव प्रकाश और सौदान सिंह को फिर राष्ट्रीय सह महामंत्री (संगठन) की जिम्मेदारी दी गयी है। विनोद तावड़े, सुनील बंसल, विप्लव देव, स्मृति ईरानी, सतीश पूनिया, गजेन्द्र पटेल, हरिश द्विवेदी, संजय भाटिया राष्ट्रीय महासचिव होंगे। पीयूष गोयल राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। पार्टी ने कुल 7 राज्यों से 8 महामंत्री बनाए हैं और सबसे ज्यादा दो नेता उत्तर प्रदेश से आते हैं। चार महिलाओं को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है।

राष्ट्रीय मंत्री का दायित्व कविता पाटीदार, के सुरेंद्रन, भोला सिंह, प्रदीप वर्मा, जगदीश ईश्वर भाई पटेल, संदीप पाठक, फार्मोनो कोन्यक, संगीता यादव, अनिल एंटनी, एम वेंकटेशन , राम मोघव, बैजयंत जय पांडा, डी

जय प्रकाश को सौंपा गया है। वहीं, तरुण चुग को राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी और महेन्द्र पांडे को राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री बनाया गया है। डॉ. संवित पात्रा को नॉर्थ ईस्ट संयोजक बनाया गया है। प्रकोष्ठ संकुल संयोजक विष्णु दत्त शर्मा को बनाया गया है। इस प्रकोष्ठ के सह संयोजक ऋतुराज और विष्णु वर्धन रेड्डी को बनाया गया है।

हेमांग जोशी को युवा मोर्चा, रूप कुमारी चौधरी को महिला मोर्चा, अमरपाल मौर्य को ओबीसी मोर्चा, बंसीलाल गुर्जर को किसान मोर्चा, शिवेश कुमार राम को अनुसूचित जाति मोर्चा, ममालाल रावत को अनुसूचित जनजाति और कुंवर बासित अली को अल्पसंख्यक मोर्चा की कमान सौंपी गई है। अनिल वल्लू को फिर मीडिया संयोजक बनाया गया है। आशीष उषा अग्रवाल, प्रदीप भंडारी, सिद्धार्थ यादव को सह संयोजक बनाया गया है। दीपक म्हस्के को सोशल मीडिया संयोजक बनाया गया है। प्रीति गांधी, शिवानंद द्विवेदी, आलोक भट्ट, अरुण यादव को सिंह, मुर्गाका देव बर्मन, रोहन गुप्ता, सह संयोजक बनाया गया है।

क्या देवेन्द्र फड़नवीस दिल्ली ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के पीछे कई संभावित कारण बताए जा रहे हैं। इनमें तीन बार मुख्यमंत्री के रूप में उनका मजबूत प्रदर्शन, नागपुर से उनका संबंध और आरएसएस से उनके करीबी रिश्ते प्रमुख हैं। इसके अलावा, विपक्षी नेताओं की ओर भी से बार-बार यह दावा किया जाता रहा है कि उन्हें केन्द्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, तथा शिखा जैसे किसी महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जा सकती है।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की समय-समय पर होने वाली चर्चाओं और केन्द्र में अनुभवी प्रशासकों की भाजपा की जरूरत ने भी इन अटकलों को लगातार हवा दी है।

बहरहाल, प्रधानमंत्री मोदी के साथ फड़णवीस की मुलाकात ने उनके राष्ट्रीय स्तर पर संभावित भविष्य को लेकर लंबे समय से चल रही चर्चाओं को फिर से जीवित कर दिया है।

वंदे मातरम् का ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मुख्यालय इंदिरा भवन में ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया।

पहले दो अंतरे गाए जाने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे ने सोनिया गांधी से कहा कि गीत गाया जा चुका है और इतना पर्याप्त है। सोनिया गांधी ने इसके बाद राहुल गांधी से कहा कि खड्गे जी कुछ कह रहे हैं, उनकी बात सुनो।

राहुल गांधी ने उन्हें समझाया कि कांग्रेस के कुछ लोगों को पूरा वंदे मातरम् गाने पर आपत्ति है और ध्वजारोहण से पहले इस मुद्दे पर चर्चा भी हुई थी।

इसके बाद तय किया गया कि चूंकि अब इसे कानून का रूप दे दिया गया है, इसलिए पूरा गीत गाया जाएगा।

और इंदिरा भवन में ठीक यही हुआ।

इससे पहले सोनिया गांधी को इशारे करते हुए देखा गया कि वे कुछ कैमरा संचालकों से वहां से हटने और कार्यक्रम की कार्यवाही में बाधा न

डालने के लिए कह रही थीं।

मामला यहीं समाप्त हो गया। लेकिन अमित शाह ने इस मुद्दे को बड़ा राजनीतिक विवाद बना दिया है। वे सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी पर वंदे मातरम् को रोकने की कोशिश करने का आरोप लगा रहे हैं और इसके लिए माफी मांगने की बात कर रहे हैं।

वे केवल माफी ही नहीं चाहते, बल्कि उन्होंने दिल्ली पुलिस से पूरे घटनाक्रम की जांच करने और यह रिपोर्ट देने को भी कहा है कि क्या कानून का उल्लंघन हुआ है। एक बेहद खूबसूरत देशभक्ति गीत को नफरत और दुश्मनी की राजनीति में घसीटकर भाजपा द्वारा हिंदू बनाम मुस्लिम विभाजन की आग को जलाए रखने और उससे अधिकतम राजनीतिक लाभ हासिल करने की कोशिश की जा रही है।

वंदे मातरम् की शुरुआत कांग्रेस के साथ हुई थी और अब भाजपा इस आग को जलाए रखने के लिए पूरी ताकत लगा रही है, ताकि इससे अधिकतम राजनीतिक लाभ उठाया जा सके।